●वर्ष-5

●अंक-298

रायपुर, शुक्रवार
31 जुलाई 2026

●पृष्ठ-8

●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज–8>> शिक्षा जीवन बदलने की सबसे ...

पेपर नहीं हुआ था लीक सवाल कराए गए थे याद

सीबीआई की चार्जशीट में और कौन-कौन से हुए खुलासे?

नईदिल्ली। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस बार पारंपरिक तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि प्रश्नपत्र तैयार करने और उसका अनुवाद करने की जिम्मेदारी संभाल रहे तीन विशेषज्ञों ने कथित तौर पर अंतिम सवाल याद कर उन्हें अपने ट्यूशन के चुनिंदा छात्रों तक पहुंचाया। बाद में यही सवाल बिचौलियों के जरिए लाखों रुपये लेकर कई राज्यों में बेचे गए। मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर दी है, जबकि एनटीए की परीक्षा प्रणाली में भी एक बड़ी खामी की ओर इशारा किया गया है।

सवाल तैयार करने और अनुवाद में क्या थी बड़ी चूक?: सूत्रों ने बताया कि नीट परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने और उनका अनुवाद करने की प्रक्रिया में एक ही तरह के लोगों की भागीदारी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी की प्रमुख वजहों में से एक रही। सीबीआई ने अनौपचारिक रूप से इस कमी की जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दी है और संभावना है कि इसे अपनी औपचारिक सिफारिशों में भी शामिल करेगी।

2024 और 2026 की गड़बड़ियों में क्या अंतर था?: प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नीट-यूजी 2026 में सामने आई गड़बड़ियां 2024 की घटनाओं से पूरी तरह अलग थीं। वर्ष 2024 में एक परीक्षा केंद्र प्रभारी पर कथित तौर पर पेपर लीक गिरोह के साथ मिलकर प्रश्नपत्र की चोरी और उसे फैलाने में मदद करने का आरोप था।

2024 के बाद एनटीए ने कौन-कौन से सुधार किए थे?: अधिकारियों ने बताया कि 2024 की जांच के बाद सीबीआई ने एनटीए को प्रश्नपत्र के परिवहन, उसकी सुरक्षा, हैंडलिंग और परीक्षा संचालन से जुड़े कई संस्थागत सुधारों की सिफारिश की थी। एनटीए ने 2025 और 2026 की परीक्षाओं में इन सुझावों को लागू भी किया। इसी वजह से तकनीकी रूप से इस बार पारंपरिक अर्थों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।तीन शिक्षकों ने कथित तौर पर कैसे याद किए अंतिम सवाल?: सूत्रों के अनुसार, एनटीए पैनल के जिन विशेषज्ञों को प्रश्न तैयार करने और मराठी में उनका अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें केमिस्ट्री शिक्षक पी.वी. कुलकर्णी, फिजिक्स शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी शिक्षिका मनीषा संजय हवलदार शामिल थे। आरोप है कि इन तीनों ने अंतिम प्रश्नपत्र के सवाल याद कर लिए और बाद में पुणे स्थित अपनी ट्यूशन क्लास में पढ़ने वाले चुनिंदा छात्रों के साथ उन्हें साझा किया। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये शिक्षक प्रश्नपत्र तैयार करने और अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल थे। 3 मई को आयोजित परीक्षा से पहले उन्हें अंतिम प्रश्नपत्र के साथ कथित तौर पर काफी समय% मिला था।

राज्यसभा से भी लोक परीक्षा विधेयक पास विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

नई दिल्ली। आज संसद के मानसून सत्र का नौवां दिन है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित कर दी गई। दोपहर तीन बजे तक के लिए निचले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई। वंदेमातरम् बिल यहां से भी पास कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। खरगे के मनुस्मृति वाले बयान पर खूब हंगामा भी हुआ।

राज्यसभा ने गुरुवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मतदान के दौरान विपक्षी सांसद जॉन ब्रिटास, ए.ए. रहीम, हारिस बीरान और संतोष कुमार पी. की ओर से बिल की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए दिए गए नोटिस पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि वे उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। वहीं, सांसद पी. विल्सन और तिरुची शिवा ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन सदन ने उन्हें

खारिज कर दिया। इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट

एंटी पेपर लीक पर राज्यसभा में देर रात तक चर्चा जारी है। मंत्री जितेंद्र सिंह के संबोधन के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक पर राघव चड्ढा ने भी बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा ठीक है। आपका आवाज उठाना भी ठीक है। जब आपने अपनी चिंता व्यक्त की आपनी मांगे बताई तो पीएम मोदी ने परिवार के मुखिया की तरह उनकी बाते सुनी। तुरंत एक्शन भी लिया।

राज्यसभा में लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी बात रखी।

जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना

राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मैंने सुबह ही कहा था कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और आज उनके व्यवहार ने यह साबित भी कर दिया। करीब आठ घंटे तक चर्चा चली और हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। सत्ता पक्ष ने सभी बातों को गंभीरता से सुना। लेकिन जब मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया। यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।

कुर्सी बचाने के लिए लाया गया एंटी पेपर लीक बिल : खड़गे

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि नीट का पेपर लीक होने के बाद कई मासूम छात्रों और उनके माता-पिता को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स अमेंडमेंट बिल, 2026' का स्वागत करते हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। केंद्र सरकार को देश में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए।

पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थाई रोक लगाने के लिए सरकार ने मेटा से मांगा विस्तृत जवाब

नईदिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार के सामने पेश होकर पीएम नरेंद्र मोदी की उस पोस्ट के लिए विस्तृत जवाब देने को कहा है, जिस पर कुछ समय के लिए फेसबुक ने अस्थाई रोक लगा दी थी। यह बैठक अगले सात से 10 दिनों के बीच हो सकती है। इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस.कृष्णन ने कहा कि सरकार मामले को पूरी तरह से समझने के लिए मेटा

से नीतिगत स्तर और तकनीकी स्तर दोनों प्रकार का स्पष्टीकरण लेना चाहती है।उन्होंने कहा,भारत अपनी चिंताएं सीधे मेटा तक पहुंचाना चाहता है और उन हालात के बारे में पूरी जानकारी चाहता है जिनकी वजह से यह अस्थायी रोक लगाई गई थी।

कृष्णन ने बताया, मेटा ने इस घटना पर पहले ही खेद जताया है और सरकार को शुरुआती स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह भी शामिल है कि कंपनी ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है।यह नया कदम सरकार द्वारा मेटा के एक सीनियर अधिकारी को बुलाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह बुलावा प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगने के बाद भेजा गया था।

रायपुर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पैरा एथलेटिक्स 100 मीटर टी-47 स्पर्धा में दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण पदक के साथ नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित कर भारत का गौरव बढ़ाया है, वहीं मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीतकर देश को एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि दिलाई है। दोनों खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन भारतीय पैरा एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत और क्षमता का परिचायक है।

सिलीगुड़ी कॉलेज हिंसा: गिरफ्तार टीएमसी छात्र नेता पर अदालत परिसर में फेंके गए अंडे

सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कालेज में दो माह पहले हुई हिंसक झड़प के मामले में गिरफ्तार तृणमूल छात्र परिषद के नेता सौरभ भाष्कर उर्फ मर्डर को अदालत परिसर में विरोध का सामना करना पड़ा।हाजत से कोर्ट रूम ले जाते और वापस लाते समय उस पर अंडे फेंके गए। इस दौरान अदालत परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभालते हुए आरोपित को सुरक्षित अदालत में पेश किया।सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने अशांति फैलाने और मारपीट के आरोप में सौरभ भाष्कर को गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। कालेज हिंसा की घटना के बीते 22 मई को हुई थी। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, राज्य में सत्ता परिवर्तन के करीब 20 दिन बाद कालेजों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। नए छात्र-छात्राओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क लगाने को लेकर सिलीगुड़ी कालेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।

प्रमुख समाचार

पंजाब पेपर लीक: दिल्ली भाजपा का आप कार्यालय पर प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के कैनिंग लेन स्थित कार्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की राजनीति में दोहरे मानदंडों के विरोध में था। भाजपा ने पंजाब में हुए अनेक परीक्षा प्रश्नपत्र रिसाव

मामलों को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस की बर्खास्तगी की मांग की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी, जिन्हें पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले गई और एक घंटे बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र और दोहरी राजनीति को बेनकाब करने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में प्रश्नपत्र रिसाव का मुद्दा उठने पर आप ने हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। मल्होत्रा ने पूछा कि पंजाब में पिछले 4-5 साल में हुए प्रश्नपत्र रिसाव पर आप चुप क्यों है। उन्होंने कहा, केंद्र में इस्तीफा, पंजाब में संरक्षण- यही है आप का दोहरा चरित्र।

शाह पर गंभीर आरोपों के लिए राहुल माफी माँगें : कंगना

नईदिल्ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को मांग की कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें। 20 जुलाई को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री को

ज़िम्मेदार ठहराने वाले गांधी के बयानों पर पत्रकारों से बात करते हुए, कंगना रनौत ने कहा कि बिना सबूत के ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते। बीजेपी सांसद ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) माफ़ी मांगनी होगी। आप इस तरह झूठ नहीं फैला सकते और किसी पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। राज्यसभा में पेश किए जाने वाले सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रस्तावित कानून शिक्षा प्रणाली की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को हल करने में विफल रहा है।

हॉकी इंडिया की जर्सी का रंग बदलने पर भड़कीं प्रियंका

नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर भगवा किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चाहे वे जर्सी का रंग बदलें या शिक्षा नीति के जरिये इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करें, वे

चाहे जो भी करें। आपने देखा है कि हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं। आपने जंतर-मंतर पर जुटे युवाओं की बात सुनी है। यह देश की आवाज है। प्रियंका गांधी ने कहा, अहिंसा और सत्य पर इस देश की आजादी की लड़ाई की नींव रखी गई थी। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कोई भूमिका नहीं थी। पूरा देश इस सच्चाई को जानता है। जिन लोगों को नहीं पता था, उनको आज पता चल रहा कि इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस देश की आत्मा अहिंसा, सत्य और भाईचारे पर आधारित है। इसे कोई नहीं छीन सकता, न आरएसएस और न ही कोई और।

शिक्षा में भ्रष्टाचार गहरा कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार बहुत गहरा है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसकी अखंडता को बहाल करने की लंबी यात्रा में सिर्फ पहला कदम है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया

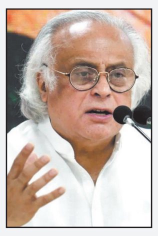

रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के प्रमुख संस्थानों में इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में हेरफेर के आरोपों से जुड़े एक घोटाले का खुलासा हुआ है। रमेश ने एक्स पर कहा, भारत की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार बहुत गहरा है। शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा इसकी अखंडता को बहाल करने की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के परिणामों और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों में अंतर रहा है। रमेश ने कहा कि एमएच-सीईटी में टॉप करने वाले छात्र बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।

अखिलेश यादव के बयान से यूपी में आया सियासी भूचाल

नईदिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके संगी-साथी आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध के दोषी हैं। उन्होंने दान, चढ़ावे और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए इसे संसद में ले जाने की बात कही। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, जो भाजपा का साथी, वो रामघाती-महापापी। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े दान-पात्र, गुप्त दान, दान की रसीदों और जमीन खरीद-फरोख्त में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने कम कीमत पर जमीन खरीदकर उसे कई गुना अधिक कीमत पर मंदिर ट्रस्ट को बेचकर लाभ कमाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदार लोगों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया और पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं का हुआ विशेष सम्मान

राष्ट्रपति भवन के विशेष अतिथि बने बस्तर के मांझी-चालकी

रायपुर। बस्तर की लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व की गौरवशाली विरासत ने आज राष्ट्रपति भवन में इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडुम-2026 के विजेता प्रतिभागियों, परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में आत्मीय स्वागत किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं, परगना मांझी, मांझी, चालकी तथा पद्मश्री सम्मानित विभूतियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में अत्यंत दुर्लभ और आत्मीय दृश्य तब देखने को मिला, जब राष्ट्रपति ने स्वयं सभी अतिथियों को भोजन परोसकर उनका सम्मान किया। राष्ट्रपति की इस सहज आत्मीयता ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया।

प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, बस्तर के पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व के प्रतिनिधि, बस्तर पंडुम-2026 के विजेता कलाकार, पद्मश्री सम्मानित विभूतियाँ, जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से आत्मीय

संवाद करते हुए बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोककला, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, मांझी-चालकी प्रणाली तथा बस्तर पंडुम के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कलाकारों और जनजातीय प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत भारत की अमूल्य धरोहर है और उसका संरक्षण पूरे देश का दायित्व है।

राष्ट्रपति ने जताई बस्तर आने की इच्छा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भविष्य में बस्तर दशहरा एवं बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा उनके हृदय को विशेष रूप से स्पर्श करता है। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ की काष्ठ निर्मित प्रतिमा तथा बस्तर दशहरा की अद्वितीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बस्तर दशहरा से विशेष आत्मीय संबंध रहा है।राष्ट्रपति ने कहा कि मांझी उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनके पिता भी मांझी थे। जनजातीय समाज की परंपरागत नेतृत्व व्यवस्था सामाजिक एकता, सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक संरक्षण की सशक्त आधारशिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों और स्थानीय जनभागीदारी के परिणामस्वरूप बस्तर आज शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर में आया यह सकारात्मक परिवर्तन पूरे देश के लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है। उन्होंने मांझी एवं चालकी की भूमिका की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि वे समाज और प्रशासन के बीच प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण : सीएम साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से बस्तर के प्रतिनिधिमंडल की यह आत्मीय भेंट पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर अंचल के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का

विषय है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएँ और सांस्कृतिक विरासत देश के सर्वोच्च संवैधानिक मंच पर सम्मानित हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर आज शांति, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा दिलाई है तथा स्थानीय कलाकारों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को नया मंच प्रदान किया है।उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति से गहरा आत्मीय जुड़ाव है। उनके अनुभव, स्नेह और मार्गदर्शन से बस्तर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा मिलेगी।मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि उनके आगमन से बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक पहचान मिलेगी तथा जनजातीय समाज का उत्साह और बढ़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन का भ्रमण भी किया तथा भारत की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक विरासत से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हुआ।

उफनती नदी पार कर जगा रहे शिक्षा की अलख, हर दिन जान जोखिम में डालते हैं शिक्षक

जगदलपुर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड में शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। यहां रोज उफनती कोटरी नदी को नाव के सहारे पार कर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। बरसात के दौरान हमेशा ऐसे ही हालात रहते हैं। कोयलीबेड़ा विकासखंड का यह दृश्य सिर्फ एक नदी पार करने का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की जमीनी चुनौतियों की तस्वीर है। शिक्षकों को पहले नाव मिलने का इंतजार करना पड़ता है, फिर नदी पार कर पैदल कई किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है।उफनती कोटरी नदी में तेज बहाव और बड़े-बड़े पत्थरों के बीच नाव चलाना किसी खतरे से कम नहीं है। वीडियो में शिक्षक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हर दिन डर के साये में सफर करना पड़ता है, और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई बार इंटरनेट नेटवर्क भी काम नहीं करता, जिससे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने और विभागीय कामकाज में भी परेशानी होती है।शिक्षकों का कहना है कि जिला प्रशासन को कम से कम लाइफ जैकेट जैसी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, वही शिक्षक अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर कर्तव्य निभा रहे हैं।

गौठान में बाढ़ के पानी में फंसा परिवार

नगर सेना ने टॉर्च की रोशनी में किया रेस्क्यू, 300 मवेशी अब भी संकट में

गरियाबंद। लगातार हो रही बारिश के बीच गरियाबंद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी की सांसें रोक दीं। सुहागपुर के गौठान में बाढ़ के पानी से घिरे एक परिवार को नगर सेना की टीम ने चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि उसी गौठान में करीब 300 गायें अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसी हुई हैं।

दरअसल, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले के सुहागपुर गांव को संकट में डाल दिया। गौठान में बुधवार दोपहर से एक परिवार बाढ़ के पानी के बीच फंसा हुआ था। शाम करीब पांच बजे इसकी सूचना जिला प्रशासन और नगर सेना की टीम को मिली। हालात इतने खराब थे कि गौठान तक पैदल पहुंचना संभव नहीं था। इसके बाद रेस्क्यू बोट मंगाई गई और देर शाम शुरू हुआ ऑपरेशन रात तक चलता रहा।

नगर सेना के जवानों ने आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी बोट से तय की। कई बार बोट बीच रास्ते में बंद भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ खड़े जवान टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाते रहे। आखिरकार करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।रेस्क्यू किए गए परिवार में 5 साल, 3 साल और 2 साल के मासूम बच्चे भी शामिल थे।

जैसे ही पूरा परिवार सुरक्षित किनारे पहुंचा, मौके पर मौजूद लोगों ने 'जय बजरंगबली' के जयकारे लगाए। घंटों तक मौत के साये में रहने के बाद परिवार के चेहरों पर राहत और मुस्कान साफ दिखाई दी। यह ऑपरेशन जिले के इतिहास का पहला ऐसा देर रात फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, जिसे नगर सेना की टीम ने पूरी सफलता के साथ पूरा किया। मौके पर थाना प्रभारी, तहसीलदार और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे।हालांकि पांच लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सुहागपुर गौठान में करीब 300 गायें अभी भी बाढ़ के पानी के बीच फंसी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा गौठान पानी से घिर चुका है। जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।नगर सेना की टीम ने सिर्फ इस परिवार की ही जान नहीं बचाई। इससे पहले दोपहर में भी भिलाई स्थित एक फार्म हाउस से तीन लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के पानी में फंसे इन लोगों को भी नगर सेना की टीम ने समय रहते बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिलहाल सुहागपुर में हालात पर जिला प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती अब गौठान में फंसी करीब 300 गायों को सुरक्षित निकालने की है।

नारायणपुर में बाढ़: ग्राम चिकपाल में फंसे ग्रामीणों को किया रेस्क्यू

नारायणपुर। बस्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब नारायणपुर और बीजापुर जिले का है। नारायणपुर के धौड़ाई थाना इलाके में भारी बारिश की वजह से ग्राम चिकपाल में कई ग्रामीण बाढ़ के पानी में फंस गए।

खबर मिलते ही बाढ़ के पानी में फंसे सभी 16 ग्रामीणों को बोट की मदद से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम में नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी के जवान शामिल रहे। जिन 16 लोगों को जवानों ने रेस्क्यू किया उसमें 7 बच्चे, तीन महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। समय पर पर बचाव दल के पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस अधीक्षक की ओर से भी बताया गया है कि जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस ने अपील जारी करते हुए कहा है कि लोग नदी नालों का रुख नहीं करें। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है तो उसकी तत्काल जानकारी जिला प्रशासन या राहत बचाव कार्य में जुड़ी टीम को दें। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदी-नाले उफान पर हैं, अनेक मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी लगातार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रही है, जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा है।

सभी विभागों में ई-ऑफिस का अनिवार्य एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें : कलेक्टर

शहीद जवानों के सम्मान में उनके नाम पर चौक-चौराहों एवं विद्यालयों के नामकरण हेतु चिन्हांकन के निर्देश

नारायणपुर। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर नम्रता जैन की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को ई-ऑफिस का अनिवार्य एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं जवाबदेह बनाने के लिए सभी नस्तियों एवं पत्रावलियों का ई-ऑफिस के माध्यम से समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जिले के शहीद जवानों के सम्मान ,सर्वोच्च बलिदान एवं योगदान को स्मरणीय बनाने में उनके नाम पर चौक-चौराहों एवं विद्यालयों के नामकरण के लिए उपयुक्त स्थलों का शीघ्र चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। बस्तर मुन्ने एवं नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वीकृत आवासों एवं निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सेवा सेतु के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा करते हुए सर्वेक्षित स्थानों पर शीघ्र मोबाइल टॉवर स्थापित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा स्कूली बच्चों की शत-प्रतिशत मलेरिया जांच कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम डॉ. सुमित गर्ग, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुनील कुमार सोनपिपरे, तहसीलदार सौरभ चौरसिया, विजय साहू, जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्रनाथ पाण्डेय तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अरपा भैंसाझार परियोजना में गड़बड़ी

प्रारंभिक जांच में 11 एसडीएम पर गलत मुआवजा बांटने का आरोप, अब दोबारा होगी जांच

बिलासपुर। अरपा भैंसाझार परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है। परियोजना के दस्तावेजों की विस्तृत जांच में तत्कालीन 11 एसडीएम द्वारा नियमों के विपरीत मुआवजा वितरण किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में लगभग 27 करोड़ रुपये की गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब संभागायुक्त ने मामले की दोबारा जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की है।

जांच समिति में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई ईडी द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर की गई है।

दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि परियोजना से प्रभावित 104 गांवों में से 75 गांवों में भूमि अर्जन और मुआवजा वितरण के दौरान कई मामलों में नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि भूमि के प्रकार, पात्रता और मूल्यांकन में त्रुटियां करते हुए कई लोगों को गलत तरीके से अधिक मुआवजा दिया गया। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, तत्कालीन एसडीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कई प्रकरणों में वित्तीय अनियमितताएं हुईं।

प्रारंभिक कार्रवाई के तहत अब तक केवल एक अधिकारी को निलंबित किया गया है, जबकि अन्य अधिकारियों को राहत मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच रिपोर्ट में कई अधिकारियों के नाम सामने आने के बावजूद सीमित कार्रवाई को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

नई गठित समिति को मुआवजा वितरण, भूमि अर्जन की प्रक्रिया, फसलों के मूल्यांकन, प्रभावित किसानों की पात्रता, रिकॉर्ड में किए गए संशोधन, बाउंड्री निर्धारण तथा राजस्व अभिलेखों में हुई प्रविष्टियों की बिंदुवार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही।

अरपा भैंसाझार परियोजना बिलासपुर जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है। ऐसे में करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरे मामले पर प्रशासनिक और राजनीतिक नजरें टिक गई हैं। अब सभी की निगाहें चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि अनियमितताओं के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, और दोषियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नगरसेना ने बीमार बच्ची व मां को उपचार के लिए पहुंचाया अस्पताल

बीजापुर। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगरसेना की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। ग्राम रेड्डी की एक महिला एवं उसकी बीमार बच्ची को उफनते जलमार्ग से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जिससे उन्हें समय पर उपचार मिल सका। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनते नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन और नगरसेना की सहायता लें। टीम आवश्यकता पडने् पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, अस्पताल ले जाने तथा आपदा की स्थिति में त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे तत्पर है। लगातार हो रही बारिश के बीच टीम का यह मानवीय और साहसिक प्रयास लोगों के लिए राहत का बड़ा सहारा बन रहा है। प्रशासन द्वारा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत एवं बचाव दल पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहे हैं।

ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

कांकेर। जिले की भानुप्रतापपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन के माध्यम से सट्टा संचालित करने वाले तीन आरोपियों विकास उर्फ रिंकू सॉरी निवासी बसंत नगर तथा मनोज सचदेव निवासी संतोषी नगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं, वहीं उनके बैंक खातों में जमा 6.88 लाख की राशि को होल्ड कर कार्रवाई उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसपर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया आरोपियों के खिलाफ थाना भानुप्रतापपुर में अपराध क्रमांक 147/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 7(1) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन जब्त किए। साथ ही ऑनलाइन सट्टे से जुड़े बैंक खातों में जमा 6.88 लाख की राशि को होल्ड कर दिया।

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में महिला थाना की मांग

एमसीबी। जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर पृथक महिला थाना स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बुधवार को कांग्रेस की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह को ज्ञापन सौंपकर जिले में जल्द से जल्द महिला थाना खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और पीड़िताओं की समस्याओं को देखते हुए अलग महिला थाना समय की जरूरत बन गया है। महिला कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि एमसीबी जिला 9 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था, लेकिन लगभग चार वर्ष बीत जाने के बाद भी जिले में पृथक महिला थाना स्थापित नहीं किया गया है। इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद और अन्य महिला संबंधी मामलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें सामान्य थानों में जाना पड़ता है, जहां कई बार वे असहज महसूस करती हैं और खुलकर अपनी बात नहीं रख पातीं।

कोरबा में पीएम फसल बीमा योजना से क्यों दूर हैं किसान

कोरबा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों की आर्थिक सुरक्षा का कवच माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इस योजना की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस खरीफ सीजन में जिले के केवल 9,800 किसानों ने ही अपनी फसलों का बीमा कराया है। विडंबना यह है कि पिछले वर्ष इसी अवधि में करीब 23,000 किसानों ने बीमा कराया था। यानी एक साल के भीतर बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अंतिम कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान रुचि नहीं ले रहे हैं। अब तक जिले के 9889 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अपनी फसल का बीमा कर लिया है। पिछले बार सामने 23000 किसानों का बीमा किया था, अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हमने सभी फील्ड अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है।

दुर्ग पुलिस ने 26 म्यूल खाताधारक को गिरफ्तार किया

दुर्ग भिलाई। दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी में प्रयुक्त 26 म्यूल बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय साइबर के निर्देश पर भिलाई नगर थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के संदिग्ध खातों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि इन खातों में साइबर ठगी से प्राप्त रकम सीधे जमा की गई थी, जिससे इन्हें लेयर-1 की श्रेणी में रखा गया। वर्ष 2024 से 2026 के बीच इन खातों के जरिए ठगी की राशि अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर करने और नकद निकासी के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि खाताधारकों ने अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल सिम और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं अन्य लोगों को उपलब्ध कराईं, जिनका उपयोग साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम को छिपाने, स्थानांतरित करने और अवैध आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया।

एससीईआरटी की किताब में चमकी खैरागढ़ की कला

कक्षा 8वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे धरम-मनीषा की बनाई शैल-कलाकृतियां

खैरागढ़। खैरागढ़ की कला को एक और बड़ी पहचान मिली है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), छत्तीसगढ़ की कक्षा 8वीं की सहायक वाचन पुस्तक में खैरागढ़ के युवा कलाकार दंपति धरम नेताम और मनीषा नेताम की बनाई गई शैल-कलाकृतियों को शामिल किया गया है। अब प्रदेशभर के लाखों स्कूली विद्यार्थी उनकी बनाई कलाकृतियों के जरिए इतिहास, विज्ञान और कला का अनोखा संगम पढ़ेंगे।

मनेंद्रगढ़ का गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। इसी पार्क को आकर्षक और जीवंत बनाने के लिए धरम और मनीषा ने प्राकृतिक चट्टानों पर 37 शैल-कलाकृतियां तैयार कीं। इनमें डायनासोर, प्रागैतिहासिक समुद्री जीव और उस दौर के प्राकृतिक वातावरण को पत्थरों पर बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। इन्हीं कलाकृतियों को अब स्ष्टश्वक्रञ्ज ने अपनी पाठ्यपुस्तक में जगह दी है।

धरम नेताम बताते हैं कि यह काम किसी चुनौती से कम नहीं था। प्राकृतिक चट्टानों पर काम करते हुए मौसम, पत्थरों की बनावट और तकनीकी मुश्किलों के बीच करीब 90 दिनों तक लगातार मेहनत करनी पड़ी। हर आकृति बनाने से पहले वैज्ञानिक तथ्यों और प्राचीन जीवों का गहन अध्ययन किया गया, ताकि कलाकृतियां वास्तविकता के सबसे करीब हों।

धरम नेताम और मनीषा नेताम दोनों ने राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (क्ख्न) और वर्ष 2017 में स्कल्पचर विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। वर्षों की मेहनत और कला के प्रति समर्पण का ही नतीजा है कि आज उनका काम राज्य की स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन गया है। कला नगरी के रूप में पहचान रखने वाले खैरागढ़ के लिए यह उपलब्धि गर्व की बात है। यह सिर्फ दो कलाकारों की सफलता नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कला परंपरा का सम्मान है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कलाकृतियां विद्यार्थियों में इतिहास, भूविज्ञान, पर्यावरण और शिल्पकला के प्रति रुचि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अब खैरागढ़ के इन कलाकारों की पहचान सिर्फ प्रदर्शनियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेशभर के लाखों विद्यार्थी उनकी कला से सीखेंगे और प्रेरणा भी लेंगे। यह उपलब्धि बताती है कि समर्पण और सृजनशीलता से स्थानीय प्रतिभाएं भी अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं।

कवर्धा के गांवों में मलेरिया का प्रकोप

अबतक 20 हजार ग्रामीणों की जांच, करीब 45 मरीज

कवर्धा। बैगा बाहुल्य गांव मुड़वाही सहित आसपास के गांवों में मलेरिया का प्रकोप है। करीब 15 दिनों से गांवों में लगातार मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन गांवों में विशेष जांच अभियान चला रहा है, जिसमें अब तक 40 से 45 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों का दावा है कि हाल के दिनों में पांच लोगों की मौत भी हुई है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को मलेरिया से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। बारिश के मौसम में बोड़ला ब्लॉक के मुडवाही,सोनवानी, जामुनपानी, बहानाखोदरा और बालसमुंद गांवों में बुखार और मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया गया। अब तक 20 हजार से ज्यादा ग्रामीणों की जांच की जा चुकी है। संक्रमित मरीजों में बच्चों की संख्या भी शामिल है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 मरीजों को झलमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था।इनमें से अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि कुछ का इलाज अभी जारी है। विभाग का कहना है कि गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और चिकित्सा टीम लगातार निगरानी कर रही है।

बीएमओ डॉ। पुरुषोत्तम ने बताया कि संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ग्रामीणों को साफ-सफाई बनाए रखने, मच्छरों से बचाव करने, मच्छरदानी का उपयोग करने और उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

श्रावण मास के शुभारंभ पर वित्त मंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने देवाधिदेव महादेव की आराधना के पावन पर्व श्रावण मास के शुभारंभ पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की उपासना, श्रद्धा, भक्ति, संयम और आध्यात्मिक साधना का पवित्र अवसर है। यह पावन मास प्रत्येक श्रद्धालु के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक शांति और लोककल्याण की भावना का संचार करता है। श्री चौधरी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो तथा प्रदेश निरंतर विकास, खुशहाली और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेशवासियों से श्रावण मास के दौरान श्रद्धा एवं आस्था के साथ भगवान शिव की आराधना करने तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और सेवा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कामना की कि महादेव का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे और यह पावन मास सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सुख एवं मंगल लेकर आए।

सड़क हादसे में घायल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली रेफर

रायपुर। उत्तरप्रदेश के ललितपुर में हुए सड़क

हादसे में घायल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को बेहतर इलाज के लिए गुरुवार सुबह झांसी से दिल्ली रेफर किया गया। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक किरण सिंह देव की हालत खतरे से बाहर है। उनके पैर और कमर में चोट आई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव बुधवार को उत्तरप्रदेश में सड़क हादसे के शिकार हुए थे। हादसा झांसी-ललितपुर हाईवे पर उस समय हुआ था, जब वह परिवार के साथ बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। उन्हें तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।

छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर बैन! छापेमारी के बाद स्वास्थ्य मंत्री का फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब एनालॉग पनीर की बिक्री नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि आज के बाद छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर नहीं बिकेगा। इसके लिए जल्द आदेश जारी हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार नकली पनीर की शिकायत मिल रही थी। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना रखा था, जिसके बाद से प्रदेशभर में नकली पनीर के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। इस बीच अब स्वास्थ्य मंत्री ने एनालॉग पनीर पर बैन लगाने का फैसला लिया है। एनालॉग पनीर एक प्रकार से नकली या सिंथेटिक पनीर है, जिसे दूध के बजाय वनस्पति तेल (पाम ऑयल) और स्टार्च से बनाया जाता है। यह दिखने और स्वाद में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन यह पोषक तत्वों से रहित होता है।

वित्त मंत्री चौधरी ने किया जीके इलेक्ट्रिक शोरूम का शुभारंभ

रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित जीके इलेक्ट्रिक शोरूम का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शोरूम का अवलोकन किया तथा संचालकों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ निरंतर विकास और व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। नए प्रतिष्ठानों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उपभोक्ताओं को बेहतर एवं आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शोरूम क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिकल उत्पाद और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेगा। श्री चौधरी ने शोरूम संचालकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि व्यापार जगत की प्रगति से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलती है, जिससे समग्र विकास को बल मिलता है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, व्यापारीगण, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

सपनई व्यपवर्तन योजना के कार्यों के लिए 6.55 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़-शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा, रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-रायगढ़ की सपनई व्यपवर्तन योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर की लाईनिंग कार्य के लिए 6 करोड़ 55 लाख 59 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूरा हो जाने पर क्षेत्र में कुल 810 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। योजना के अंतर्गत कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

मलेरिया से एक भी मौत न हो, इस दिशा में सरकार कर रही काम : स्वास्थ्य मंत्री

■ **श्याम बिहारी जायसवाल ने माना- राज्य में तीन लोगों की हुई मलेरिया से मौत**

रायपुर। हाल में राज्य में तीन लोगों की मलेरिया से मौत हुई है, इसे छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक भी मौत मलेरिया से न हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कही।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया। मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मलेरिया नियंत्रण में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मॉडल बना। कभी बस्तर की पहचान मलेरिया जैसी गंभीर चुनौती से होती थी। लेकिन आज वहीं क्षेत्र मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की सफलता का राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभरा है।

उन्होंने बताया कि सरकार की रणनीतिक कार्ययोजना, स्वास्थ्य विभाग के सतत् प्रयासों एवं जनसहभागिता के परिणामस्वरूप घर-घर सर्वेक्षण, समय पर जाँच, त्वरित उपचार, प्रभावी वेक्टर नियंत्रण तथा व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बस्तर संभाग की मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.60 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत रह गई है। जबकि राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक 5.21 से घटकर 0.90 पर पहुँच गया है।

श्याम बिहारी ने बताया कि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2025 तक मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 16.97 लाख कीटनाशकयुक्त मच्छरदानियों का वितरण कर मलेरिया नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया। इन उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सम्मानित किया गया है।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि बस्तर जहाँ लोगों ने दवा, नर्स, डॉक्टर नहीं देखे थे, उन्हें घर पहुंच इलाज मिल रहा है। नक्सलवाद के वजह विकास बाधित था। नक्सलवाद मुक्ति के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान चलाया गया, जिसमें 34 लाख से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचा।

उन्होंने कहा कि बीमारी देखे, खून चेक किया गया, बीमारी पकड़ में आई, फिर इलाज कराया गया और कुछ का इलाज जारी है। 60 हजार मरीजों को रेफर उच्च हॉस्पिटल भेजा गया। 10 हजार से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर काम किया गया। दो सालों में एक हज़ार डॉक्टरों की भर्ती की गई है। मातृत्व मृत्यु दर 142 से घट कर 122 हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाओं

के विकास की जिक्र करते हुए कहा कि अति महत्वपूर्ण 3 नवीन मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के लिए निर्धारित कार्य किया गया है। जिनकी लागत क्रमशः राशि 321.71 करोड़, रुपए, 322.85 करोड़ रुपए, 321.80। करोड़ रुपए (कुल लागत राशि 966.36 करोड़ रुपए है। जिन्हें दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्षित किया गया है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चार नवीन चिकित्सा महाविद्यालय भवन, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम एवं गीदम (दंतेवाड़ा) का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। जिसका निर्माण लागत क्रमशः राशि 362.586 करोड़ रुपए, 357.247 करोड़ रुपए, 357.247 करोड़ रुपए एवं राशि 366.515 करोड़ रुपए मिलाकर कुल लागत राशि 1443.57 करोड़ रुपए है।

इसके साथ बताया कि निर्माणाधीन चारों नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण त्वरित गति से किया जा रहा है। आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिला जशपुर के कुनकुरी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय सृजन एवं निर्माण कार्य के लिए राशि 359.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा की कार्रवाई अंतिम चरण में है। आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करने के लिए लक्षित किया गया है।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के कोनी में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान एवं चिकित्सालय के अधोसंरचना एवं चिकित्सा सुविधाओं में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए कोनी जिला बिलासपुर में भवन निर्माण एवं अधोसंरचना कार्य के लिए राशि 1412.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

मंत्री ने बताया कि रायपुर स्थित डॉ। भीमराव अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय में 700 बेड एकीकृत चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 376.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निविदा दर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा बिलासपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए 93.24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कार्य प्रगतिरत पर है, जिसको नवम्बर 2027 में पूर्ण करने का लक्षित किया गया है।

राज्य में कुल 14 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय, जिसमें 11 नर्सिंग महाविद्यालय एवं 3 नर्सिंग एवं छात्रावास शामिल हैं, के निर्माण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 5 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय का कार्य प्रगतिरत है, वहीं 10 नर्सिंग महाविद्यालय निर्माण कार्य का कार्यदेश जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 2 कार्य मनेन्द्रगढ़ एवं सारंगढ़-बिलैगढ़ के सरिया की निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

मंत्री ने बताया कि जिला अस्पताल, मनेन्द्रगढ़, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-गंडई, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 190 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड अस्पताल का कार्य त्वरित गति से प्रगतिरत है। मनेन्द्रगढ़ एवं कुनकुरी में 220 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य 72.25 करोड़ रुपए की लागत से त्वरित गति से प्रगतिरत है।

उन्होंने बताया कि रायपुर जिले के सरोना और धमतरी जिला के कुरूद, कोरबा जिला के कटघोरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सरिया में 100 बेड अस्पताल का कार्य त्वरित गति से प्रगतिरत है। इसके साथ जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जिला महासमुंद के बसना एवं रायपुर जिला के राखी नवा रायपुर में 100 बेड अस्पताल का कार्य का कार्यादेश जारी किया गया है। जिला रायगढ़ के पुसौर, जिला-गरियाबंद एवं जिला बेमेतरा में 100 बेड अस्पताल का कार्य निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसकी कुल लागत राशि रू। 180.44 करोड़ का कार्य प्रारंभ किया गया है।

मंत्री चौधरी ने किया कबीर कुटीर सामुदायिक भवन का लोकार्पण

रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 35 (कबीर चौक के पास) नवनिर्मित सामुदायिक भवन कबीर कुटीर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कबीर दास जी का जीवन और विचार आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कबीर जी केवल संत नहीं, बल्कि महान समाज सुधारक और दूरदर्शी चिंतक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में पनिका-महंत समाज से अपने बचपन के आत्मीय संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के लोगों से उनका रिश्ता वर्षों पुराना है और वे हमेशा समाज की उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर जो प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना और अन्य युवाओं को भी आगे लाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने युवाओं से सुनियोजित तरीके से शिक्षा ग्रहण करने और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर संघ लोक सेवा आयोग (क्क्रस्ष्ट) की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को दिल्ली में रहकर कोचिंग प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने युवाओं से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में पिछले ढाई-तीन वर्षों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। अनेक बड़े विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और विभिन्न चरणों में हैं, जिनका लाभ आने वाले समय में जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए लगातार प्रयास और कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा वे प्रतिदिन क्षेत्र के विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं।

कार्यक्रम में समाज की ओर से छात्रावास की मांग रखे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी समाजों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने रायगढ़ में संचालित श्प्रयासश् आवासीय संस्थान तथा कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम में रायगढ़ नगर निगम के महापौर श्री जीवर्धन चौहान, नगर निगम सभापति श्री डिग्रीलाल साहू, जिला पनिका-महंत समाज के अध्यक्ष श्री गोपाल दास महंत सहित जिला पनिका-महंत समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

भूपेश बघेल को सेक्स सीडी कांड मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सेक्स सीडी कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है।

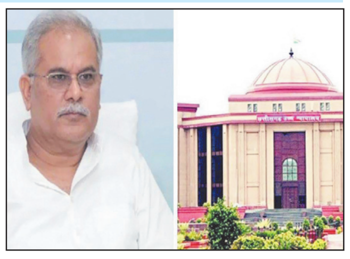

भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने अपने पूर्व के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करते हुए बघेल के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

याचिका में भूपेश बघेल की ओर से विशेष अदालत के उस आदेश पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को निरस्त कर उनके खिलाफ मामले में आरोप तय करने की दिशा में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे फिलहाल बघेल के खिलाफ इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्तर पर आगे की प्रक्रिया थम गई है।

बम-बम भोले की गूंज, शिव भक्त निकालेंगे कांवड़ यात्रा

रायपुर। गुरुवार से चहुं ओर बम-बम भोले की गूंज सुनाई पडने् लगी है। शिव मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अब महीने पर चलेगा। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भगवान शिव के भक्तों की सबसे बड़ी और धार्मिक कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। शिव भक्त पवित्र नदियों के तटों पर पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। इस दौरान भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लेकर हर-हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा करके शिव मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन के महीने की शुरूआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरूआत हो जाती है। इस बार आज से यानी की 30 जुलाई 2026 से सावन माह की शुरूआत हुई है।

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला, तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का ताप अधिक बढ़ गया।भगवान शिव के शरीर के ताप और जलन को शांत करने के लिए देवताओं और परम शिव भक्त रावण ने पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तभी से सावन महीने में गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने और कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा चल रही है।

मुख्यमंत्री साय की बड़ी सौगात : बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली तक बनेगी 4.89 करोड़ की सड़क

बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण को मिली प्रशासनिक स्वीकृति, ग्रामीणों में खुशी की लहर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना विकास को लगातार गति मिल रही है। इसी क्रम में जिले के बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस सड़क का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांगों में शामिल थी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान होगा।

नई सड़क बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। विशेष रूप से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और गांवों की जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुंच अधिक सुगम हो सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़क संपर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सड़क परियोजनाएं न केवल आवागमन को सुगम बना रही हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली सड़क निर्माण की यह स्वीकृति क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से नदियां-नाले उफान पर

■ **वर्षाजनित घटनाओं में 5 लोगों की मौत**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, नदियां और नाले उफान पर हैं तथा कई स्थानों पर सड़क संपर्क बाधित होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि वर्षाजनित विभिन्न घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने बताया कि रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में कई सड़कें जलमग्न हैं और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए परामर्श जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गरियाबंद जिले में बुधवार को 55 वर्षीय एक व्यक्ति सहसपुर गांव के पास उफनते सरगी नाले को पार करते समय बह गया।

उन्होंने बताया कि उसका शव करीब पांच किलोमीटर दूर खुटेरी गांव के पास बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जिले में सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रायपुर को पड़ोसी ओडिशा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-130 जलभराव के कारण बंद है।

इसके अलावा गरियाबंद-महासमुंद, गरियाबंद-नगरी-धमतरी और कोचबाय-मालगांव-कसानाला मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। गरियाबंद के जिलाधिकारी भगवान सिंह उइके ने कहा कि लगातार बारिश के कारण जिले की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सिकासार बांध के 21 में से 16 फाटक खोल दिए गए हैं और 58,000 क्यूसेक पानी की आवक के मुकाबले 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर पंतोरा स्थित शासकीय बालिका आवासीय विद्यालय की 50 से अधिक छात्राओं को

सुरक्षित बारुका गांव भेजा गया है। साथ ही पैरी नदी के किनारे बसे गांवों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उइके ने बताया कि गरियाबंद जिला अस्पताल परिसर में लगभग तीन फुट पानी भर गया है, जबकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

पड़ोसी धमतरी जिले में जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जलाशय का जलस्तर बढ़ने पर सोंढूर बांध के फाटक खोल दिए गए हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 26 जुलाई को लाट नाले के पुल को पार करते समय कार सहित बह गए दंपति के शव बुधवार को बरामद कर लिए गए। उनकी कार चिखली गांव के पास लगभग 150 मीटर नीचे मिली।

एक अन्य घटना में, दोस्तों के साथ घूमने गए दुर्ग-भिलाई के 20 वर्षीय युवक का शव बुधवार को लगभग 24 घंटे चले बचाव अभियान के बाद सक्ती जिले के दमऊधारा जलप्रपात से बरामद किया गया। वह तेज बहाव में बह गया था। बीजापुर जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं।

इससे बीजापुर-भैरमगढ़ और बीजापुर-गंगालूर मार्ग सहित कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मंगलवार को बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक किसान की मौत हो गई थी।

जिला प्रशासन ने लोगों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने तथा उफनती नदियों, नालों और जलमग्न पुलों को पार नहीं करने की सलाह दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश होने तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है।

साथियों को भूखे मरता छोड़ जश्न मनाती सीजेपी

राकेश सैन

गिद्धों का भी एक धर्म होता है, वो जिंदा जानवरों का मांस नहीं खातीं। वह प्रतीक्षा करती हैं उसके मरने की और प्राण छोड़ने के बाद ही लोथड़ों को नोचती हैं। लेकिन आज का इंसान गिद्ध से भी ज्यादा विभत्स हो गया लगता है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्राण गंवाने वाले 21 युवाओं के पोस्टर लगा कर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेता इन युवाओं का शोक मनाना तो दूर बल्कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद फाइव स्टार होटलों में कुल्हे मटकाते और बोतलों के ढक्कन खोलते दिखे। पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो गया और लगभग एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र के रखवालों की नई-नई रखवाली कॉकरोच जनता पार्टी का धरना भी खत्म हो गया पर दो दिनों के भीतर ही इन नए नवेले लोकतंत्र के रखवालों का असली चेहरा सामने आने लगा है। नीट पेपर लीक होने के आक्रोश में मारे गए, जिन युवाओं के पोस्टर लगा कर कोहराम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने इतना तमाशा किया वो अपने साथियों को भूखे मरता छोड़ खुद फाइव स्टार होटलों में ठुमके लगाते और बीयर पार्टी करते हुए दिखाई दिए। लाशों के मंच पर लग रहे ठुमके और उड़ रही शराब की दुर्गंध इस बात की साक्षी है कि इस तरह की हरकत करने वालों के मनों में कितनी सड़ांध भरी होगी। केवल आम जनता ही नहीं बल्कि खुद सीजेपी के आंदोलन से जुड़े साथियों ने इसे शर्मनाक बताया है। सीजेपी के मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने वायरल वीडियो को लेकर कहा है कि जीत के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। सोनम ने कहा कि सफलता पाने के साथ-साथ सम्मान और विनम्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सीजेपी समर्थकों ने भी पार्टी के वीडियो की आलोचना की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य और कमेंटेटर-यूट्यूबर मेघनाद ने सीजेपी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारी सड़कों पर बेघर और भूखे रह गए थे तब ये नेता पार्टी कर रहे थे। इंस्टाग्राम पोस्ट में मेघनाद ने कहा कि उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने उन दर्जनों प्रदर्शनकारियों के लिए यात्रा और भोजन का इंतजाम किया जो सीजेपी नेताओं के साथ एक महीने से ज्यादा समय से जंतर-मंतर पर डेरा डाले हुए थे। मेघनाद ने सीजेपी पार्टी के वीडियो के बारे में लिखा, 'मैं यह सुबह 4 बजे देख रहा हूं। मैंने और कुछ लोगों ने पिछले दो दिनों में अपने पैसे से सीजेपी के उन वॉलंटियर्स और प्रदर्शनकारियों को घर भेजा है जिन्हें बेसहारा और भूखा छोड़ दिया गया था। मैं कुछ नहीं कहने वाला था लेकिन मैंने यह वीडियो देखा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।' उन्होंने सीजेपी के लिए कड़े शब्दों के साथ अपनी पोस्ट खत्म की, 'जब आप पार्टी कर रहे थे तब दिल्ली में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और छात्र भूखे रह गए क्योंकि आपने परवाह न करने का फैसला किया था। बधाई हो सीजेपी आखिरकार आप भी एक और राजनीतिक पार्टी बन ही गए।' ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन के खत्म होने के दो दिन बाद ही उसमें फूट पड़ती दिख रही हो। आखिर पड़े भी क्यों ना, कुछ लोगों ने देश के युवाओं के आक्रोश का लाभ उठाया और देखते ही देखते वे दुनिया में अभियानवादियों के स्टार बन गए। उनकी कही बातें अब इंटरनेशनल मीडिया में गूंज रही हैं और उनकी भाव भंगिमा ऐसी है मानो उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो। लेकिन क्या फाइव स्टार होटलों में गुलछर्रे उड़ाने वाले जेन-जी नेता बताएंगे कि आंदोलन के दौरान कितनी बार पेपर लीक के मृतकों को याद किया गया।

राहुल की राजनीति में शब्दों की सीमा और आरोपों की जिम्मेदारी

कांतिलाल मांडोत

भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का सफर लगातार बदलाव के दौर से गुजरता दिखाई देता है। कभी पारिवारिक विरासत के सहारे राजनीति में आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष अब स्वयं अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से लेकर रायबरेली और हिंदी पट्टी के दूसरे हिस्सों तक उनकी सक्रियता यह संकेत देती रही है कि वे कांग्रेस की पुरानी जमीन को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक संघर्ष केवल यात्राओं, रोड शो और जनता से संवाद तक सीमित नहीं होता। संसद के भीतर इस्तेमाल किए गए शब्द और लगाए गए आरोप भी किसी नेता की राजनीतिक छवि को उतना ही प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही दिखाई देती है कि वे अपने राजनीतिक आक्रामक तेवर और संसदीय मर्यादा के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं।

राहुल गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्वत:स्फूर्तता मानी जाती है। वे अक्सर तैयार भाषण से हटकर अपने मन की बात कह देते हैं। यही अंदाज कभी उन्हें जनता से जोड़ता है तो कभी विवादों में भी ले जाता है। संसद में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने जिस तरह आपत्ति जताई, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि विपक्ष के नेता को सरकार पर हमला करते समय भाषा की सीमा कितनी सावधानी से तय करनी चाहिए।

पेपर लीक का मुद्दा निश्चित रूप से देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायतें और परीक्षा प्रक्रिया पर उठते सवाल युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे मुद्दे पर संसद में सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है और परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। उन्होंने पेपर लीक के लिए बड़ी रकम के लेन-देन का भी आरोप लगाया और शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

लेकिन गंभीर विषय उठाने और गंभीर आरोप लगाने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। आरोप यदि तथ्य और प्रमाण के साथ लगाए जाएं तो वे सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन वही आरोप जब राजनीतिक भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ सामने आते हैं तो मूल मुद्दा पीछे छूट सकता है। संसद में राहुल गांधी के बयान के दौरान यही स्थिति देखने को मिली। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 'इडियट' जैसे शब्दों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की और लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदन की मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यहां सवाल केवल एक शब्द का नहीं है। सवाल यह है कि क्या संसद में राजनीतिक असहमति व्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा आवश्यक है। लोकतंत्र में तीखी आलोचना की पूरी गुंजाइश है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। मंत्री की कार्यशैली पर सवाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और अपमानजनक शब्द लोकतांत्रिक बहस को कमजोर ही करते हैं।

राहुल गांधी के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अब केवल कांग्रेस के एक सामान्य सांसद नहीं हैं। वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। इस पद के साथ राजनीतिक अधिकारों के साथ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी जुड़ी है। देश के करोड़ों लोग संसद की कार्यवाही देखते हैं और विपक्ष के नेता की बात को सामान्य राजनीतिक बयान से अधिक गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए राहुल गांधी की भाषा का प्रभाव भी व्यापक होता है।

सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर जिस तरह हमला किया, उसमें राजनीति का स्वाभाविक तत्व भी दिखाई देता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के नेता की भाषा को अनुचित बताया और कहा कि देश के युवाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि राहुल गांधी बिना पर्याप्त प्रमाण के गंभीर आरोप लगाकर केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का तर्क है कि पेपर लीक का मुद्दा पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच बहस का विषय रहा है तथा अब राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है।

लेकिन सरकार को भी यह समझना होगा कि विपक्ष के सवालों को केवल राजनीतिक अवसरवाद कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यदि छात्रों के मन में परीक्षा व्यवस्था को लेकर अविश्वास है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शी तरीके से जवाब दे। कितने पेपर लीक हुए, जांच कहां तक पहुंची, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है, इन सवालों के स्पष्ट उत्तर जनता को मिलने चाहिए। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि विपक्ष मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है।

इसी तरह राहुल गांधी को भी यह समझना होगा कि आरोप लगाना आसान है लेकिन आरोप को प्रमाणित करना कठिन। खासकर जब बात गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ हो। राहुल गांधी की ओर से गोली या पैलेट गन चलाने के आदेश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे आरोपों के लिए ठोस प्रमाण अपेक्षित हैं। संसद में किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाने के बाद उससे जुड़े तथ्य सामने रखना विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी है। यदि प्रमाण नहीं हैं तो आरोप राजनीतिक बहस को तो गर्म कर सकते हैं लेकिन उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

राजनीति में राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी स्वत:स्फूर्त शैली को बनाए रखते हुए राजनीतिक और संसदीय जिम्मेदारी का संतुलन कायम करें। उनके समर्थक उनके बेबाक अंदाज को उनकी ताकत मानते हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी बिना किसी डर के सरकार से सवाल करते हैं और युवाओं, किसानों तथा आम लोगों के मुद्दों को संसद में उठाते हैं। दूसरी ओर उनके आलोचक कहते हैं कि वे कई बार जल्दबाजी में ऐसे बयान दे देते हैं जिन्हें बाद में सरकार और भाजपा उनके खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है।

दोनों पक्षों के बीच यह बहस भारतीय लोकतंत्र के लिए नई नहीं है। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के आरोपों में राजनीति देखता है और विपक्ष सरकार के जवाबों में बचाव। लेकिन लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि आरोप और जवाब दोनों तथ्य आधारित हों। संसद राजनीतिक युद्ध का मैदान जरूर है लेकिन वह केवल नारेबाजी और व्यक्तिगत आरोपों का मंच नहीं हो सकती।

राहुल गांधी के सामने इसलिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर भी है। यदि वे पेपर लीक जैसे मुद्दों को लगातार तथ्य और प्रमाण के साथ उठाते हैं, छात्रों की समस्याओं को नीति के सवाल से जोड़ते हैं और सरकार से ठोस जवाब मांगते हैं तो उनकी भूमिका प्रभावी विपक्षी नेता के रूप में और मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि गंभीर मुद्दों के बीच व्यक्तिगत टिप्पणियां और बिना प्रमाण के आरोप हावी हो गए तो बहस का केंद्र छात्रों की समस्या से हटकर राहुल गांधी की भाषा बन जाएगा। संसद में हाल की घटना इसी खतरे की ओर संकेत करती है।

कांग्रेस के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को केवल राजनीतिक रूप से आक्रामक नेता के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदार विपक्ष के चेहरे के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। परिवार की विरासत राजनीति में शुरुआती पहचान दे सकती है लेकिन लंबे समय की राजनीतिक विश्वसनीयता केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन से बनती है। जनता यह देखती है कि नेता क्या सवाल पूछता है, कैसे पूछता है और उसके सवालों के पीछे कितनी तैयारी है।

राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में यह दौर निर्णायक हो सकता है। वे कांग्रेस की पुरानी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष के नेता के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में उनके शब्द ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। संसद में सरकार को कठघरे में खड़ा करना उनका अधिकार है लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी भी है।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

ठीक और भू-विवर आदि शब्दों का तथा तत्तत्परिमाणद्योतक योजन आदि इसी तरह पौराणिक भूगोल प्रयुक्त भू-मण्डल, भूवलय, द्वीप, समुद्र शब्दों का पुराण-सम्मत पारुभिाषिक अर्थ जान लेने पर भी वे वे सब सन्देह काफूर हो जायेंगे जो कि उक्त शब्दों को लोकप्रसिद्ध मानने की दशा में प्राय: उत्पन्न होते हैं।

भू-मण्डल शब्द का परिभाषार्थ

भूमण्डल का शब्दार्थ चाहे कुछ भी हो, परन्तु पुराण ग्रन्थों में इस शब्द की निम्नलिखित परिभाषा नियत की गई है-

...भू-मण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते।

(श्रीमद्भागवत 5 ।16 ।1)

अर्थात्- भगवान् सूयं जितनी दूर तक ताप दान करते हैं और जिस स्थान में तारागणों सहित वह चन्द्रमा दीख पड़ता है उतने विस्तृत स्थान को भूमण्डल कहते हैं।

अब जा लोग पौराणिक भूगोल को पढ़ते हुये तदुर्वाणत समुद्र-नन नदी सरोवरों किंवा पर्वतों को इस दृश्यमान छोटी सी भूमि पर ही देखना चाहते हैं उन्हें आँख खोल कर ऊपर लिखी पंक्तियें पढ़नी चाहियें। जब कि पौराणिक भूगोल के प्रथम शब्द भूमण्डल की परिभाषा में ही यह व्यक्त कर दिया गया है कि पौराणिक भूगोल का क्षेत्र केवल यह भूपिण्डमात्र ही नहीं है बल्कि जहां तक सूर्य्यदेव तपते हैं और जहाँ ज्योतिश्चक्रसहित चन्द्र भगवान् दीख पड़ते हैं उतने लम्बे चौड़े विस्तृत आकाश-स्थल के अभ्यन्तरवर्ती समस्त पदार्थों को यथावत् प्रकट करना ही पुराणों का ध्येय है तब भूपिण्डमात्र में सब कुछ ढूंढने की चेष्टा करना और न मिलने पर पुराणों का दोष बतलाना मूर्खता नहीं तो और क्या है?

क्रमशः ...

मुंशी प्रेमचंद

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उनको उपन्यास सम्राट और कलम का जादूगर कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को यथार्थवादी रंगों से जीवंत किया। उनका जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। बता दें कि हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का कद काफी ऊंचा माना जाता है।

वाराणसी के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। जब प्रेमचंद 7 साल के थे, तो उनके सिर से मां का साया उठ गया था। वहीं उनके पिता ने दूसरी महिला से शादी कर ली। लेकिन फिर 15 साल की उम्र में प्रेमचंद अपने पिता को भी खो बैठे।

उन्होंने साल 1908 में सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित किया। जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। फिर साल 1918 में सेवासदन ने उनको हिंदी साहित्य स्थापित किया। वहीं साल 1918-1936 का कालखंड प्रेमचंद युग कहलाया।

बता दें कि प्रेमचंद की रचनाएं पंच परमेश्वर, गोदान, कफन, पूस की रात आदि सामाजिक कुरीतियों और मानवीय संवेदना को उजागर करने का काम करती हैं। प्रेमचंद के दूसरे विवाह ने उनको भावनात्मक स्थिरता देने के साथ उनके निजी रिश्ते को भी संवारा और इससे प्रेमचंद की लेखनी भी समृद्ध हुई।

प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू में 18 से ज्यादा उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी थीं। जोकि आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की कृतियां हिंदी साहित्य में अमर हैं और उनकी लेखनी आज भी लेखकों को प्रेरित करने का काम करती हैं।

प्रेमचंद की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित थी। अलंकारों और मुहावरों ने उन्हें सजीवता प्रदान की। इनकी भाषा के कारण इनकी रचना के सभी पात्र व चरित्र हमारे समक्ष सजीव हो उठते हैं। यही इनकी भाषा की सबसे बड़ी ताकत है। इनकी भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य है।

प्रेमचंद सबसे पहले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलिस्मी दुनिया से बाहर निकाला और अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। प्रेमचंद एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया। प्रेमचंद ने अपने पात्रों का चुनाव समाज के उपेक्षित वर्ग से अधिक किया है। उन्होंने अपनी कहानियों में भारत के वंचित शोषित, दलित, पिछड़े और गरीब किसानों के लिए संघर्ष वर्णित किया है। उनकी कहानियां दलितों व स्त्रियों के दुःखों को उजागर ही नहीं करतीं, बल्कि उसे मार्मिक भी बना देती हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अक्षुण्ण बनाये रखने वाले कहानीकारों में प्रेमचंद अग्रणी हैं। प्रेमचंद का लेखन उनके इस कथन को पूरी तरह से चरितार्थ करता है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है।

वहीं 08 अक्तूबर 1936 को पेचिश रोग के कारण प्रेमचंद का निधन हो गया था।

पाकिस्तान में होने वाला है सीजेपी जैसा आंदोलन?

अभिनय आकाश

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए तद्दठु के प्रदर्शनों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा सुधारों के वादे के साथ ही यह जन-आंदोलन तो थम गया, लेकिन भारत भी दक्षिण एशिया के उन देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है जहाँ छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने सियासी कुर्सी को हिला कर रख दिया। साल 2022 से 2025 के बीच छात्रों के आंदोलन से बांग्लादेश और नेपाल में में सरकारें गिरी, इंडोनेशिया में मंत्रियों की वीआईपी सुविधाएं छीनी गई, कई रिफॉर्म हुए। अब भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन छात्रों के इन आंदोलनों से अछूता रहा । हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, लेकिन भला क्यों? आखिर श्रीलंका से लेकर भारत तक दक्षिण एशिया को मथ देने वाली यह युवा क्रांति रेडक्लिफ रेखा के उस पार जाकर क्यों थम जाती है? क्यों पाकिस्तान में छात्र आंदोलन उस तरह इतिहास नहीं बदल पा रहे हैं जैसे उसके पड़ोसियों में हुआ?

दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देशों के उलट, पाकिस्तान में छात्र राजनीति की कोई मज़बूत परंपरा नहीं है। यह भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से बिल्कुल अलग है, जहाँ बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अपने असरदार छात्र और युवा संगठन बनाए रखती हैं। ये संगठन राजनीतिक गतिविधियों को संगठित और सक्रिय करने का काम करते हैं और हाल के युवा-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। माइकल कुगेलमैन के अनुसार, इसकी जड़ें काफी हद तक जनरल ज़िया-उल-हक के सैन्य शासन की विरासत से जुड़ी हैं, जिसने छात्र राजनीति पर रोक लगा दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा जनरल ज़िया ने 1980 के दशक में छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ज़्यादातर मामलों में उन्हें फिर से बहाल नहीं किया गया है। पाकिस्तान में युवाओं की बड़ी आबादी और एक्टिविज़्म में छात्रों/युवाओं की अहम भूमिका को देखते हुए, उस प्रतिबंध के असर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रतिबंध से पहले पाकिस्तान में छात्र राजनीति खूब फल-फूल रही थी। 1968-69 के बड़े जन-आंदोलन में छात्र समूह सबसे आगे थे; इस आंदोलन के कारण राष्ट्रपति अयूब खान को महीनों तक चले देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा था। हालाँकि, ज़िया के शासनकाल में छात्र यूनियनों को दबाने की कार्रवाई एक अहम मोड़ साबित हुई, जिससे राजनीतिक लामबंदी के केंद्र के तौर पर कैंपस की भूमिका कमज़ोर पड़ गई। तब से, पाकिस्तान में युवाओं के नेतृत्व वाले बहुत कम देशव्यापी आंदोलन हुए हैं। एक उल्लेखनीय अपवाद स्टूडेंट्स सॉलिडैरिटी मार्च था, जो 2018 से 2022 के बीच हर साल आयोजित किया गया। इसमें छात्र यूनियनों को बहाल करने और छात्रों को ज़्यादा अधिकार देने की मांग की गई थी। कार्यकर्ताओं की बार-बार की मांगों के बावजूद, छात्र यूनियनों पर प्रतिबंध ज़्यादातर बना हुआ है। नतीजतन, पाकिस्तान में उस तरह के संगठित कैंपस नेटवर्क का अभाव है, जिन्होंने दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में युवा आंदोलनों को मज़बूती दी है।

पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती देने वाले विरोध आंदोलनों की कोई कमी नहीं है। बलूचिस्तान में, कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा प्रांतीय स्वायत्तता, ज़बरदस्ती लोगों को गायब करने की प्रथा को खत्म करने और प्रांत की विशाल खनिज संपदा में उचित हिस्सेदारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए हैं, हालांकि उनके अभियान अक्सर लंबे समय से चल रहे हिंसक बलूच विद्रोह की वजह से दब जाते हैं। इसी तरह, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में अशांति की लहर देखी गई है। इस कमेटी ने बिजली की बढ़ती कीमतों से लेकर शरणार्थियों के लिए विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित करने जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। हालांकि, अहम फ़र्क यह है कि ये आंदोलन ज़्यादातर अपने-अपने इलाकों और मुद्दों तक ही सीमित रहे हैं। पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों में युवाओं के नेतृत्व में हुए आंदोलनों के उलट, ये आंदोलन एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन में नहीं बदल पाए हैं जो इस्लामाबाद को चुनौती दे सके। पाकिस्तान के कई युवा भी इसी बात से सहमत हैं। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए, एक युवा ने कहा कि भारत में सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से सबसे बड़ी सीख यह मिली कि प्रदर्शनकारी एक साझा मकसद के लिए एकजुट हो सकते हैं। पाकिस्तान में छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स और यहां तक कि अखबारों के संपादकीय लेखों ने भी सीजेपी के नेतृत्व वाले Gen Z आंदोलन की तारीफ़ की है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर भी, युवाओं को एकजुट करने में सक्षम मज़बूत संगठनों की कमी और पाकिस्तान के मौजूदा विरोध आंदोलनों के एक संयुक्त मोर्चे के रूप में एकजुट होने में असमर्थ या अनिच्छुक होने के कारण, ऐसा नहीं लगता कि देश की Gen Z उस तरह के युवा-नेतृत्व वाले विद्रोहों को दोहरा पाएगी जिन्होंने बाकी दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है।

हाल ही में साउथ एशिया में हुए सभी प्रदर्शन नेपाल में बांग्लादेश में, श्रीलंका में इन सब का जो संदर्भ था वो अलग-अलग था। जैसे नेपाल में करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा था। जब सोशल मीडिया में मंत्रियों के बच्चों की आलीशान जिंदगी दिखने लगी तो सरकार ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। फिर आंदोलन भड़का और हिंसा के बाद वहां सरकार गिरी नेपाल में। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में शेख हसीना ने सेना से जुड़े हुए सेना के जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन दे रही थी। इसलिए आम छात्रों ने इसका विरोध किया और जब प्रदर्शनकारियों पर क्रैक डाउन हुआ तो हिंसा भड़क गई और फिर शेख हसीना की भी वहां से सरकार चली गई। उसी तरह इंडोनेशिया में सरकार के मंत्रियों के वीआईपी प्रोटोकॉल पर उनके वीआईपी कल्चर पर पाबंदी लगाने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के बाद सरकार ने कई बदलाव किए और वहां पे उनकी मांगे मानी गई और भारत का उदाहरण तो आप जानते ही हैं कि नीट पेपर लीक में सरकार की जवाबदेही मांगी गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। यानी इन सभी देशों में आप देखिए कि आंदोलन की जो वजह है वो आपको अलग-अलग मिलेंगी। जबकि जो आंदोलन अतीत में हुए और एक दूसरे को इंस्पायर किया।

ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रदर्शन होने की कोई वजह ही नहीं है। वहां की अर्थव्यवस्था कई बरस से वेंटिलेटर में है। आईएमएफ के इंजेक्शन से वो सर्वाइव कर रही है। शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल है। चुनाव फेयर नहीं है। सेना के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। यहां तक कि न्यायपालिका पर भी वहां सवालों के घेरे में उसे लिया जा रहा है। यानी मुद्दे पर्याप्त हैं प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन सेना वहां के लोगों को आंदोलन खड़े करने का मौका ही नहीं देती है। आपने इमरान खान, गजा, ईरान या किसी पश्चिमी देश में हुई किसी घटना के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शनों के बारे में तो सुना होगा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था या रोजगार पर प्रदर्शन के बारे में अक्सर वहां से कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई खबर सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहां के आम लोग इस तरह के मुद्दों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो सीधी वजह है क्योंकि वहां की सेना क्रैक डाउन कर देती है। आखिरी बार अक्टूबर 2025 में कराची में बढ़ती महंगाई और कम वेतन की वजह से कई संगठन इकट्ठे हुए थे। इनमें सिंध एंप्लाइज एयंस एसईए सबसे आगे था। लेकिन क्या हुआ? वहां भी आंदोलन को दबा दिया गया।

आज का इतिहास

1865 दुनिया की पहली संकीर्ण गेज मेनलाइन रेलवे ग्रैंडशेस्टर ऑस्ट्रेलिया में खोला गया।

1897 माउंट सेंट एलियास, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।

1910 इंग्लैंड के क्लाउड ग्राहमे व्हाइट ने पहली बार विमान को रात में उड़ाया।

1935 मॉस्को के भूमिगत मेट्रो लाइन को लोगों के लिए खोला गया।

1937 एनिमेटड कार्टून इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड न्यूयॉर्क में लगाया गया।

1941 एडोल्फ हिटलर के निर्देशन में होलोकास्ट-अंडर हिरणरोग्रिंग ने एसएस जनरल रेनहार्ड हैडरिक को यहूदी प्रश्न के अंतिम समाधान का आदेश दिया।

1948 न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ। कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में समर्पित किया गया था।

1954 इटालियन पर्वतारोही लिनो लेसेलेली और एचीले कॉम्पानोनी हिमालय शिखर के 2 पर पहुंचने में सफल हुए।

1971 अपोलो-15 अंतरिक्ष यात्रियों ने इलेक्ट्रिक का साढ़े 6 घंटे की यात्रा की।

1972 द ट्रिबल्स-फ्री डेरी, एक स्वायत्त स्व-घोषित क्षेत्र हैडेरी, उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटिश सेना के संगठन मोटरमैन द्वारा समाप्त किया गया था।

1973 बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर डीसी-9, डेल्टा एयरलाइंस कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 89 यात्री मारे गए और एक आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गया। लेकिन अकेला जीवित रहने वाले की 6 महीने बाद मौत हो गई।

1975 द ट्रिब्यूट्स-इन बॉटेड अर्धसैनिक हमले में तीन सदस्य लोकप्रिय मियामी शोबैंड और दो उल्स्टर वालंटियर फोर्स के बंदूकधारियों को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी डाउन में मार डाला गया।

1982 यूगोस्लाविया ने कीमतों पर छह महीने के लिए रोक लगा दी।

1982 अमेरिकन यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन का गठन किया गया है। वे देश जो महासंघ के सदस्य हैं, वे फ़िनलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस हैं।

1991 सोवियत स्पेशल पर्पस पुलिस यूनिट की टुकड़ियों ने लिथुआनियाई सीमा चौकियों के खिलाफ अभियान के सबसे गंभीर हमले में मेडिनिंकाई में सातवीं रैखिक सीमा शुल्क अधिकारियों को मार डाला।

1991 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने सामरिक शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर किये।

प्रधान का इस्तीफा, जेन-जी की ताकत और राजनीति के लिए बड़ा संदेश

योगेश कुमार गोयल

भारतीय लोकतंत्र ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जनता की आवाज यदि संगठित, शांतिपूर्ण और निरंतर हो तो वह सबसे शक्तिशाली सत्ता को भी आत्ममंथन के लिए विवश कर सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं है बल्कि यह उस लोकतांत्रिक दबाव की स्वीकारोक्ति भी है, जो पिछले कई सप्ताह से देशभर के लाखों युवाओं ने अपने धैर्य, अनुशासन और दृढ़ता से निर्मित किया। हाल के घटनाक्रमों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हुई और आंदोलन के नेतृत्व ने दावा किया कि उनकी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गई। यह घटना केवल शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले वर्षों में इसे उस मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जब भारत की जेन-जी ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी से भी संचालित होता है।

इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसकी शुरुआत किसी स्थापित राजनीतिक दल ने नहीं की। यह आंदोलन सोशल मीडिया की दुनिया से निकला, व्यंग्य से शुरू हुआ और देखते ही देखते करोड़ों युवाओं की सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया। जिस 'कॉकरोच' शब्द का प्रयोग कथित रूप से अपमान के लिए किया गया था, उसी शब्द को युवाओं ने अपने आत्मसम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह अपमान को भी प्रतिरोध की शक्ति में बदल देता है। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को एक नया पाठ पढ़ाया है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाले अभियान केवल कुछ दिनों की सनसनी होते हैं लेकिन इस बार 'डिजिटल अभियान' सड़क पर उतरा, शांतिपूर्ण जनआंदोलन में बदला और अंततः सत्ता को निर्णय लेने के लिए बाध्य कर गया। इससे स्पष्ट है कि भारत की नई पीढ़ी केवल 'लाइक' और 'शेयर' तक सीमित नहीं है; वह लोकतांत्रिक भागीदारी की नई भाषा लिख रही है।

हालांकि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय केवल आंदोलन की सफलता को नहीं बल्कि उसके संयम को भी जाता है। अनेक स्थानों पर तनाव और पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन के नेतृत्व ने लगातार संवैधानिक और शांतिपूर्ण विरोध की अपील की। यही कारण है कि इस आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन मिला। लोकतंत्र में किसी भी जनआंदोलन की नैतिक शक्ति उसकी अहिंसा और अनुशासन से ही आती है। हालांकि इस जीत के साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं। क्या केवल एक मंत्री का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था की उन गहरी समस्याओं का समाधान कर देगा, जिनके कारण यह आंदोलन जन्मा? क्या प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी? क्या भर्ती परीक्षाओं में वर्षों से चली आ रही देरी खत्म हो जाएगी? क्या करोड़ों युवाओं को रोजगार की नई संभावनाएं मिल जाएंगी? इन प्रश्नों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण अवश्य है किंतु इसे अंतिम समाधान मान लेना भूल होगी। यदि परीक्षा प्रणाली की संरचनात्मक कमियां जस की तस रही, यदि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा नहीं बढ़ी, यदि दोषियों को समयबद्ध दंड नहीं मिला और यदि भर्ती प्रक्रियाएं पहले की तरह वर्षों तक अटकी रही तो आज का यह जनसंतोष भविष्य में फिर नए रूप में सामने आ सकता है। सरकार के लिए भी यह आत्मचिंतन का अवसर है। लोकतंत्र में किसी आंदोलन को केवल राजनीतिक षड्यंत्र मानकर खारिज कर देना कभी भी दूरदर्शी नीति नहीं हो सकती। शुरुआत में यदि युवाओं की शिकायतों को अधिक गंभीरता से सुना जाता, संवाद स्थापित किया जाता और सुधारों की स्पष्ट समय सीमा घोषित की जाती तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। अंततः सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और यही लोकतंत्र की सही दिशा भी है।

विपक्ष के लिए भी यह अवसर आत्ममंथन का है। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि इसकी ऊर्जा किसी पारंपरिक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि युवाओं की स्वतःस्फूर्त भागीदारी से आई। इससे स्पष्ट संदेश मिलता है कि आज की पीढ़ी केवल राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहती है। यदि विपक्ष भी केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित रहेगा और शिक्षा सुधार के ठोस एजेंडे पर गंभीरता नहीं दिखाएगा तो वह भी युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। मीडिया और खासकर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं। प्रारंभिक दिनों में आंदोलन को सोशल मीडिया की सनसनी समझने वाले अनेक मंच बाद में उसकी गंभीरता को स्वीकार करने के लिए विवश हुए। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व केवल टकराव के दृश्य दिखाना नहीं बल्कि उन कारणों की पड़ताल करना भी है, जिनके कारण लाखों युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय लोकतंत्र में एक नई राजनीतिक संस्कृति की भी शुरुआत की है। यह संस्कृति व्यक्ति-पूजा से अधिक मुद्दों पर आधारित है। यह आंदोलन किसी जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समान अवसर, निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेह शासन जैसी सार्वभौमिक लोकतांत्रिक मांगों पर आधारित था। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति रही। आज आवश्यकता इस विजय का उत्सव मनाने से अधिक उसके संदेश को समझने की है। सरकार को परीक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डिजिटल सुरक्षा, समयबद्ध भर्ती, स्वतंत्र परीक्षा नियामक और दोषियों के लिए त्वरित दंड जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देनी होगी। शिक्षा व्यवस्था में विश्वास तभी लौटेगा, जब छात्र यह महसूस करेगा कि उसकी मेहनत किसी भ्रष्ट तंत्र की भेंट नहीं चढ़ेगी। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। यही युवा आने वाले विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी हैं। यदि यही पीढ़ी व्यवस्था पर विश्वास खो दे तो किसी भी आर्थिक उपलब्धि का महत्व कम हो जाएगा लेकिन यदि यही पीढ़ी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाए, सरकार उसे सुने, विपक्ष जिम्मेदारी निभाए और संस्थाएं स्वयं को सुधारें तो यही ऊर्जा भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

बहरहाल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह लोकतंत्र की उस जीवंतता का प्रमाण है, जिसमें सत्ता से अधिक शक्तिशाली जनता का विश्वास होता है। जेन-जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि शांतिपूर्ण जनशक्ति आज भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब अगली परीक्षा सरकार की है कि क्या वह इस जनादेश को केवल एक राजनीतिक संकट मानकर भूल जाएगी या इसे शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधारों का अवसर बनाएगी? यदि इस आंदोलन से केवल चेहरा बदला और व्यवस्था नहीं बदली तो इतिहास इसे अधूरी जीत कहेगा लेकिन यदि इससे परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनी, युवाओं का भरोसा लौटा और जवाबदेही संस्थागत रूप ले सकी, तब यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में उस क्षण के रूप में दर्ज होगा, जब देश की नई पीढ़ी ने सत्ता को हराया नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत किया।

आंदोलनों को नई दिशा और गति देता सोशल मीडिया

अभिषेक कुमार सिंह

हाल के दिनों में हमारे देश में 'आउटफिट रिवील', 'फिट चेक' जैसे शब्दों ने एक नया राजनीतिक अर्थ ग्रहण किया है। सामान्यतः ये शब्द सोशल मीडिया पर अपने पहनावे को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शनों और डिजिटल अभियानों में प्रदर्शनकारियों ने इन्हें व्यंग्यात्मक शैली में अपनाया है। पुलिस बैरिकेड, गिरफ्तारी, विरोध-स्थल या प्रदर्शन के कपड़ों को 'आज का आउटफिट' बताकर साझा किया गया। इनका संदेश था कि आप 'हमारा पहनावा नहीं, हमारा प्रतिरोध देखिए'।

इस तरह सोशल मीडिया पर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली और भाषा सहज रूप से प्रतिरोध की भाषा में बदल गई। हालांकि शब्दों के ऐसे इस्तेमाल की ये घटनाएं कोई पहली बार सामने नहीं आई हैं। दुनियाभर में सोशल मीडिया की शब्दावली लगातार आंदोलनों का चेहरा बदल रही है। #ब्लैकलाइव्जमैटर, #मीटू, #फ्राइडेफॉरफ्यूचर, #वीमनलाइफफ्रीडम, #ऑक्यूपाई, #नेवरअगेन, #स्टैंडविदयूक्रेन और #फ्रीपैलेस्टाइन जैसे हैशटैग केवल इंटरनेट ट्रेंड नहीं रहे; उन्होंने वास्तविक दुनिया में लाखों लोगों को संगठित किया है, मीडिया का एजेंडा बदला है और कई देशों की राजनीतिक बहस की दिशा को प्रभावित किया।

असल में, डिजिटल समाज में किसी आंदोलन की सफलता केवल उसके उद्देश्य पर निर्भर नहीं करती; उसकी 'संचार रणनीति' भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। सोशल मीडिया एल्गोरिद्म उन सामग्रियों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं जिनमें भावनात्मक अपील, दृश्य प्रभाव और साझा करने की क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि आज आंदोलनों में कुछ विशेष डिजिटल प्रारूप तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

इन्हें विशेष रूप से इंस्टाग्राम के संदर्भों में हैशटैग एक्टिविज्म कहकर संबोधित किया जाता है। अतीत में इनमें से अलग-अलग हैशटैग विभिन्न आंदोलनों और उद्देश्यों को स्पष्ट करते रहे हैं। जैसे #ब्लैकलाइव्जमैटर और #मीटू से जुड़े आंदोलनों ने वैश्विक एकजुटता दर्शाई थी। इसी तरह #आउटफिट रिवील को विरोध और पुलिसिया कार्रवाई की मुखालफत के संदर्भ में देखा जाता है।

फोटो डंप और पीओवी वीडियो को घटनाओं की श्रृंखला और व्यक्तिगत नजरिया बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के कई और तरीके हैं, जो जटिल राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय को सरल, भावनात्मक और असरदार ढंग से साझा करने में युवाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं।

लोकतंत्र में विरोध और व्यवस्था के बीच कैसे बने संतुलन?

पीयूष पांडे

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सरकार हर मांग मान नहीं सकती, लेकिन हर मांग को अनसुना भी नहीं कर सकती। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और निर्णय, दोनों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। सरकार किसी मांग को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, उसके विरुद्ध तर्क दे सकती है या कोई वैकल्पिक रास्ता सुझा सकती है। लेकिन यदि संवाद की जगह मौन ले ले, तो असहमति अक्सर अविश्वास में बदल जाती है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार पर आरोप लगा कि उसने संवाद के बजाय मौन का रास्ता चुना और इसी कारण एक सामान्य आंदोलन व्यापक जनाक्रोश में बदल गया। उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन जंतर-मंतर पर शुरू हुआ। उस समय तक सरकार नीट की पुनर्परीक्षा करा चुकी थी। संभवतः इसी वजह से शुरुआती दिनों में वहां गिने-चुने छात्र ही पहुंचे। लेकिन छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और उग्र हो गया। इस बीच विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का अवसर मिल गया और उन्होंने भी आंदोलन को तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 21 जुलाई को राहुल गांधी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर पहुंच गए।

दरअसल, ऐसे आंदोलनों के समय सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे प्रदर्शनकारियों के सामने कब और कितना झुकें तथा दबाव की राजनीति को कितनी मान्यता दें। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण पोट्टि श्रीरामुलु का आंदोलन है। उन्होंने 19 अक्तूबर, 1952 को अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यदि सरकार किसी अनशन के दबाव में निर्णय लेने लगे, तो शासन चलाना कठिन हो जाएगा। सात दिसंबर को उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा था कि केवल इसलिए कोई मांग नहीं मानी जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति उपवास पर बैठा है, चाहे उसके परिणाम कितने भी गंभीर क्यों न हों। लेकिन जैसे-जैसे अनशन लंबा खिंचा, सरकार की चिंता बढ़ती गई। नौ दिसंबर को नेहरू ने संसद में अलग आंध्र राज्य की दिशा में कदम उठाने की बात कही, लेकिन 15 दिसंबर को श्रीरामुलु का निधन हो गया। इसके बाद हिंसा भड़की और 19 दिसंबर को सरकार ने अलग आंध्र राज्य के गठन की घोषणा कर दी। सरकार का तर्क अपनी जगह था, लेकिन इतिहास एक कठिन प्रश्न छोड़ गया—क्या जो भरोसा मृत्यु के बाद दिया गया, वह पहले नहीं दिया जा सकता था?

डॉ. भीमराव आंबेडकर की 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दी गई चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। उन्होंने कहा था, हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को त्यागना होगा। जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के सिद्धांत के

सिवाय कुछ नहीं हैं और इन्हें जितनी जल्दी त्याग दिया जाए, उतना ही बेहतर है। हालांकि, उनकी इस चेतावनी का अर्थ संवाद से इनकार करना नहीं था।

राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन राजनीति का एक पहलू अवसरवाद भी है। दिलचस्प बात यह है कि अन्ना आंदोलन के दौरान 26 अगस्त, 2011 को लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि भूख हड़ताल के जरिए संसद पर दबाव बनाकर कानून बनवाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल होगी। उनका कहना था कि यदि हर मुद्दे पर संसद को इस तरह बाध्य किया गया, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी समस्या का समाधान संवाद के बिना संभव है?

ऐसा नहीं है कि सरकार को संवाद का महत्व पता नहीं है। लेकिन उसे यह आशंका भी रहती है कि यदि एक आंदोलन से बातचीत शुरू की गई, तो हर समूह अपनी मांग मनवाने के लिए धरने का रास्ता अपना सकता है। कभी वह भीड़, मीडिया और चुनावी असर का आकलन करती है, तो कभी उसे लगता है कि आंदोलन अपने आप शांत हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर संवाद किससे किया जाए? गौरतलब है कि एक समय में आसमान में हजारों विमान उड़ते हैं, लेकिन वे टकराते नहीं क्योंकि पायलट, रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच लगातार संवाद और समन्वय बना रहता है। यदि कोई पायलट निर्देश मानने से इनकार कर दे, तो दुर्घटना लगभग तय है।

दरअसल, संवाद तभी संभव है, जब व्यवस्था बनी रहे। यदि कोई पक्ष संवैधानिक और व्यवस्थागत तरीकों के बजाय अराजक तरीकों से अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ सार्थक संवाद कठिन हो जाएगा। अराजकता संवाद की भाषा नहीं हो सकती। इतिहास के सफल आंदोलनों को देखें तो उनके पीछे वर्षों का संघर्ष और व्यापक जनसमर्थन दिखाई देता है। हालांकि, नीट पेपर लीक के विरोध में हुआ आंदोलन कई मायनों में अलग रहा। इसमें नीट से जुड़े कितने विद्यार्थी वास्तव में शामिल थे, यह अलग प्रश्न है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार को ऐसे और आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है।

दुनिया के कई देशों में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों ने राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल इसके हालिया उदाहरण हैं। लेकिन क्या भीड़ के दबाव से उभरे वे मॉडल आज सफल और स्थिर लोकतंत्र के उदाहरण हैं? यह प्रश्न अभी भी विचारणीय है। इस छात्र आंदोलन ने सोशल मीडिया एल्गोरिद्म के प्रभाव को भी सामने रखा, जो अक्सर लोगों को पूरी वास्तविकता नहीं, बल्कि उनकी पसंद के अनुरूप उसका एक छोटा हिस्सा ही दिखाता है। ऐसे में विरोध कर रहे व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। जबकि लोकतंत्र भ्रम और अराजकता से नहीं, बल्कि तथ्य, धैर्य, संवैधानिक मर्यादाओं और निरंतर संवाद से मजबूत होता है।

टेक्निकल ग्लिच या एल्गोरिदम की आड़ में मेटा कर रहा मनमानी?

अभिनय आकाश

पीएम मोदी का जेन-जी वाला वीडियो फेसबुक से गायब हो गया था। कुछ घंटों तक यूजर्स को सिर्फ ये मैसेज दिख रहा था कि लीगल रिक्वेस्ट के कारण ये वीडियो अब आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या भारत में ही प्रधानमंत्री का वीडियो ब्लॉक कर दिया गया है? मामला बढ़ने के बाद मेटा की ओर से सफाई आई और उसके बाद वीडियो भी वापस आया और कहा गया कि टेक्निकल ग्लिच था और मेटा की तरफ से माफी भी मांगी गई। हुआ ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपना सेल्फी जेन-जी वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने युवाओं से संवाद किया और नीट समेत जो बाकी कंपटेटिव एग्जाम और पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले कैबिनेट में इस विषय पर महत्वपूर्ण फैसले भी हमारी कैबिनेट लेगी। लेकिन मंगलवार तड़के 1:25 मिनट के करीब कई यूजर्स जब ये वीडियो देख रहे थे तो स्क्रीन पर नजर आ रहा था कि लीगल रिक्वेस्ट के कारण ये वीडियो अब उपलब्ध नहीं है। वीडियो के साथ एक ऑप्शन See Why का आता है यानी क्यों ये वीडियो उपलब्ध नहीं है? उस पर क्लिक करने पर यही जानकारी दिखाई दे रही थी। हालांकि नोटिस में ये नहीं बताया गया था कि किस कानून या किस सरकारी एजेंसी के रिक्वेस्ट पर वीडियो को ब्लॉक किया गया था। कुछ ही घंटों में फेसबुक पर वीडियो दोबारा से लौट आया। मेटा की ओर से साफ किया गया कि ये किसी सरकारी आदेश या कानूनी कार्रवाई का मामला नहीं था बल्कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ था। कंपनी ने इस गलती के लिए सरकार से माफी भी मांगी। मामला सामने आने के बाद भाजपा ने मेटा

पर निशाना साधा। केंद्र सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल प्रमुखों को समन जारी किया है।

जुलाई की शुरुआत में मेटा सरकार की नज़र में आ गया। बीबीसी की एक जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम यूज़र्स को ऐसे विज्ञापन और कंटेंट दिखा रहा था जो बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा देते थे। बीबीसी-आई की एक पड़ताल में पाया गया है कि इंस्टाग्राम भारत में पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन चला रहा है, जिनके ज़रिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रसार हो रहा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को मेटा से स्पष्टीकरण मांगने और उसे तलब करने का निर्देश दिया।

जुलाई में भारत ने वाट्सअप के उस नए फ़ीचर को रोल आउट करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिससे यूज़र्स यूनीक यूज़रनेम का इस्तेमाल करके चैट कर सकते थे। इसकी वजह यह थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ़िशिंग स्कैम बढ़ सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वाट्सअप का यूज़रनेम फ़ीचर लोगों को अपना फ़ोन नंबर बताए बिना चैट करने की सुविधा देता। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिस में वाट्सअप से पूछा है कि साइबर अपराध बढ़ाने वाले फ़ीचर को लॉन्च करने के लिए भारतीय क़ानून के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों न की जाए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसे लगता है कि यह फ़ीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और किसी और का रूप धरकर किए जाने वाले हमलों की घटनाओं को काफ़ी बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे अपराधी अपना फ़ोन नंबर बताए बिना संभावित पीड़ितों से संपर्क कर सकते हैं। इसके जवाब में वाट्सअप ने एक बयान में कहा कि यह फ़ीचर अभी लाइव नहीं हुआ है और इसमें सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, जैसे कि हाई-प्रोफ़ाइल यूज़रनेम को सुरक्षित रखना और किसी और का रूप धरने या धोखाधड़ी का पता लगाने के तरीक़े शामिल करना।

पिछले साल जनवरी में मेटा ने भारत से भी माफ़ी मांगी थी। यह माफ़ी तब मांगी गई जब सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने जो रोगन के पॉडकास्ट पर 2024 के भारतीय चुनावों के नतीजों को लेकर टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। ज़ुकरबर्ग ने दावा किया था कि भारत समेत कई देशों में कोविड के बाद हुए चुनावों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। भारतीय सरकारी अधिकारियों ने तुरंत इस दावे का खंडन किया। ज़ुकरबर्ग की टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के 2024 के चुनाव मौजूदा सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने निर्णायक रूप से तीसरा कार्यकाल हासिल किया। वैष्णव ने 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों के भारी मतदान का ज़िक्र किया और ज़ुकरबर्ग की बातों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। इस टिप्पणी के बाद, मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शिवनाथ ठुकराल ने एक्स पर लिखा कि मार्क की यह बात कि 2024 के चुनावों में कई मौजूदा सरकारें दोबारा नहीं चुनी गईं, कई देशों के लिए तो सही है, लेकिन भारत के लिए नहीं। ठुकराल ने इस टिप्पणी को अनजाने में हुई गलती बताते हुए खेद जताया और दोहराया कि भारत मेटा के लिए एक अहम बाज़ार बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। भारत मेटा के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है और हम इसके इनोवेटिव भविष्य का अहम हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। मेटा के लिए, भारत सरकार और न्यायपालिका के साथ ये टकराव अच्छे संकेत नहीं हैं। स्टेटिस्टा के डेटा के अनुसार, 2025 तक भारत में इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा यूज़र्स (480 मिलियन से ज़्यादा) हैं, जो अमेरिका के मुक़ाबले दोगुने से भी ज़्यादा हैं। यहाँ फ़ेसबुक के भी 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। देश में वाट्सअप की भी मज़बूत मौजूदगी है, जिसके लगभग 853 मिलियन यूज़र्स हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सअप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को साफ चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ कोई कंपनी खेल नहीं सकती। यहां तक कहा गया कि अगर नियम नहीं मान सकते, तो भारत छोड़ने का विकल्प भी खुला है। इस विवाद की जड़ वाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी थी। वाट्सअप सालों से यह कहता आ रहा है कि उसके मैसेज End-To-End Encrypted (E2EE) हैं और कोई तीसरा शख़्स उन्हें नहीं पढ़ सकता। लेकिन समस्या मैसेज के कंटेंट की नहीं, बल्कि यूज़र डेटा की है। इसी साल फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जजों ने वाट्सअप के रवैये पर सीधी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि वाट्सअप यूज़र्स को यह नहीं कह सकता कि पॉलिसी मानो या ऐप छोड़ दो। इस मामले की सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वाट्सअप की मोनोपॉली (एकाधिकार) के कारण यूज़र्स के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचता है और उन्होंने इसके डेटा से जुड़े तौर-तरीकों की तुलना निजी जानकारी की चोरी से की।

जंतर-मंतर घटना के और कितने सबक?

राजकिशोर

जंतर-मंतर की घटना ने देश को फिर दो खेमों में बांट दिया है। एक पक्ष की नजर सिर्फ पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस और दमन की तस्वीरों पर टिकी है। दूसरा पक्ष बैरिकेड टूटने, संसद की ओर बढ़ती उग्र भीड़ और सुरक्षाकर्मियों पर हुए हमलों को आधार बनाकर अपनी बात कह रहा है। दोनों अपने-अपने सच के साथ खड़े हैं, मगर लोकतंत्र को पूरे सच और संतुलन की जरूरत होती है। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अधिकार उतना ही पवित्र माना जाता है, जितना कानून का शासन। दोनों में संतुलन होना चाहिए। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, संसद की ओर कूच की नहीं। संसद की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की साझा जिम्मेदारी है। जब हजारों लोग जबरन सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब पुलिस बल के सामने कार्रवाई के अलावा व्यावहारिक रूप से बहुत सीमित विकल्प ही बचते हैं। दूसरी ओर, राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग का अधिकार बेशक प्राप्त है, पर इसे किसी भी हालत में असीमित नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस द्वारा यदि कहीं आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ हो, या पेशेवर मानकों का उल्लंघन सामने आया हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच बिना किसी देरी के होनी चाहिए। एक और चिंताजनक सवाल यह भी है कि आखिर आम जनता के बीच पुलिस की छवि लगातार क्यों धुंधली पड़ती जा रही है। यह छवि रातों-रात नहीं बिगड़ी। यह बरसों की उस दूरी का परिणाम है, जो पुलिस और आम नागरिकों के बीच बनती चली गई है। भ्रष्टाचार की घटनाएं, सुनवाई न होने की शिकायतें, इन सबने मिलकर एक ऐसी छवि गढ़ दी है, जिसमें वर्दी को अक्सर संदेह से देखा जाने लगा है। भर्ती से लेकर प्रशिक्षण तक, थाने के व्यवहार से लेकर जवाबदेही तक, हर स्तर पर सुधार की जरूरत लंबे समय से लंबित है। लोकतंत्र में पुलिस की साख व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और उसके कमजोर पड़ने का असर पूरे तंत्र पर पड़ता है। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू समाज की तरफ भी उतनी ही गंभीरता से मुड़ता है। आने वाली पीढ़ी जिस तरह अपने ही सुरक्षाकर्मियों को लेकर मीम बनाती दिखती है, जिस हल्केपन से गंभीर घटनाओं का मजाक गढ़ा जाता है और जिस तरह बिना तथ्य जाने आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है, उसे पूरे सामाजिक ताने-बाने में आ रही दरार की तरह देखा जाना चाहिए। यह सवाल केवल तकनीक या सोशल मीडिया की तेज रफ्तार का नहीं, बल्कि संस्कारों के धीरे-धीरे छीजते जाने का भी है। जो जवान सरहद और सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा होता है, उसे लेकर हंसी-ठिठोली और सतही आरोप गढ़ना किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। आलोचना और उपहास में एक बारीक, पर बहुत जरूरी रेखा होती है, जो धुंधली पड़ती दिख रही है। सवाल यह भी है कि जवाबदेही सिर्फ पुलिस की तय होगी या समाज और नागरिकों की भी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति का उल्लंघन किसने किया, बैरिकेड किसने तोड़े और सरकारी संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, इसका जवाब भी जरूरी है। संविधान ने नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए हैं, पर उसी संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी स्पष्ट उल्लेख है।

संकष्टी चतुर्थी पर इसलिए पूजे जाते हैं मंगलमूर्ति गणेश

संकष्टी चतुर्थी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कथा गणेश जी पर ही केंद्रित है। कहते हैं एक बार देवता अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के पास उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी बैठे हुए थे।

● संकष्टी चतुर्थी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कथा गणेश जी पर ही केंद्रित है। कहते हैं एक बार देवता अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के पास उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी बैठे हुए थे।

● शिवजी ने दोनों बालकों से पूछा- 'तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करेगा।' तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया।

● यह बात सुनकर शिवजी ने गणेश की इच्छा जाननी चाही। तब गणेशजी ने विनम्र भाव से कहा- 'पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूं।'

● यह सुनकर हंसते हुए शिव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी- 'जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा।'

● कार्तिकेय बडे गर्व से अपने वाहन मोर पर चढकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेशजी ने सोचा कि चूहे के बल पर तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची।

● गणेश जी 7 बार अपने माता-पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मण्डल में उनके आगे चूहे के पैरों चिह्न दिखाई दिए। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई।

● कार्तिकेय जी गणेश पर नाराज हो गए और स्वयं को पूरे भूमण्डल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश ने शिव से कहा- 'माता-पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की हैं।'

● गणेश की बात सुनकर समस्त देवताओं तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकरजी ने उन्मुक्त कण्ठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया- 'त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी।' तब गणेशजी ने पिता की आज्ञानुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया।

● जो स्त्री-पुरुष इस संकष्टी चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी का पूजन तथा चंद्र अर्ध्यदान देगा। उसका त्रिविधि ताप (दैहिक, दैविक, भौतिक) दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक में प्रणाम कर अंतर्धान हो गए।

शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। संस्कृत शब्द एकादशी का शाब्दिक का अर्थ ग्यारह होता है। एकादशी पंद्रह दिवसीय पक्ष (कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष) के ग्यारवें दिन आती है।

इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायक है

शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी के दिन व्रत करना चाहियें। यह व्रत मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। 28 अगस्त को जया एकादशी व्रत है। पुराणों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बडा महत्व बताया गया है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है । एकादशी का आरम्भ उत्पन्ना एकादशी से होता है। सी मान्यता है कि इसी एकादशी से एकादशी के व्रत की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में इसी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था।

उस देवी ने भगवान विष्णु के प्राण बचाए थे जिससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी ने इन्हें एकादशी नाम दिया। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का ब्रत रखने वाला संसार की मोहमाया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसमें बुराइयाँ समाप्त होती जाती है और एकादशी के ब्रत के पुण्य के प्रभाव से वह व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है।

एकादशी के ब्रत को सभी ब्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है । इस दिन योग्य ब्राहमणो को यथा शक्ति दान दक्षिणा भी देना चाहिए । इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। जातक को जीवन में धन, यश, आरोग्य, विघा, योग्य पुत्र , पारिवारिक सुख, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। उसके पितृ भी तर जाते है, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। जातक की आने वाली पीढियों को भी इस ब्रत का लाभ मिलता है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायक है। हिन्दु धर्म के सभी धर्म ग्रन्थ एकादशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास करने को करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी में पुण्य फलो की प्राप्ति के लिए आठ वर्ष से अस्सी वर्ष तक के सभी मनुष्यों को एकादशी के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते है वह दोपहर या संध्या काल में एक बार भोजन कर सकते हैं। परन्तु इस दिन किसी कोई भी , किसी भी रूप या स्थिति में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिये। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन मांस, प्याज, लहसुन , मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि को पूर्ण ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए ।एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन रात को सोने से पहले अच्छी तरह दाँत को साफ करके सोना चाहिए ।

एकादशी के दिन प्रात: लकडी का दातुन या मँजन न करें, वरन उँगली से कंठ को अच्छी तरह से साफ कर लें, और पानी से बारह बार कुल्ला कर लें। फिर स्नानादि कर गीता पाठ एवं उस दिन की एकादशी की कथा को पढे करें या पुरोहितजी से श्रवण करें। उस दिन ब्रत करने वाले को प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि ' आज मैं कोई भी बुरा काम, बुरा आचरण नहीं करूँगा , किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा ना ही दुष्ट मनुष्यों से बात करूँगा और रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा।'एकादशी के दिन 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादश मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन विष्णु के सहस्त्रनाम भी पाठ करें । भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि- हे ईश्वर आप मुझे इस ब्रत को विधिपूर्वक पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। इस दिन यदि भूलवश कोई बुरा आचरण हो भी जाय तो प्रभु श्रीहरि की पूजा कर उनसे क्षमा माँग लेना चाहिए। एकादशी के दिन ना तो घर में झाड़ू लगाएं और ना ही इस दिन बाल कटवाएं । इस दिन अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अधिक बोलने से मुख गलत शब्द भी निकल जाते हैं। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करते हुए मीठे, मधुर वचन ही बोलने चाहिए।

एकादशी के दिन निम्न चीजे अवश्य करे :

* एकादशी के दिन यथाशक्ति दान अवश्य ही करना चाहिए।

* इस दिन चाहे आपने ब्रत रखा हो या नहीं लेकिन आप किसी भी दूसरे मनुष्य का दिया हुआ अन्न बिलकुल भी ग्रहण न करें। ।

* ब्रत रखने वाले को एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक, कुलफा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए।

* इस दिन दूध, सेब, आम, अंगूर, मेवो में बादाम, पिस्ता , दूध इत्यादि का सेवन करें। इस दिन प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसीदल छोडकर ग्रहण करना चाहिए।

* एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन ब्राहमणों को मिष्ठान्न, दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए और उन्हें भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए । जया एकादशी व्रत से मिलती है पिशाच योनी से मुक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रहमहत्या जैसे महापाप से छूट जाता है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को पिशाच योनी से भी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के दिन पवित्र मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में द्वेष, छल-कपट, काम और वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती।

पैसों का पेड, जिस पर होना चाहिए यह चीनी सिक्का

धन और समृद्धि का सबसे प्राचीन प्रतीक मध्य में एक वर्ग छेद के साथ एक चीनी सिक्का है। ये फेंगशुई की दुकान पर मिल ही जाता है। यह सिक्का सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप इस सिक्के का उपयोग करें तो इसे पैसों के पेड पर सजा सकते हैं।व्यापक प्रतीकों में मेंढक एक खजाने पर बैठे और अपने मालिक के पास अच्छे भाग्य लाने। अपने घर में धन का क्षेत्र का स्थान है, और फेंग शुई के सिद्धांत और व्यवहार के अनुसार, पर है दक्षिण-पूर्व, जहां यह धन और समृद्धि के प्रतीक है, साथ ही तावीज और आकर्षण जगह पर व्यापार में अच्छी किस्मत को आकर्षित करती है।यह सिक्का एक ही क्षेत्र में और रखा जा सकता है। इसके अलावा फेंगशुई के अनुसार घर में पैसे के लिए लिफाफे, चीनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, लाल होना चाहिए। मौजूदा खर्च के लिए पैसे के साथ लिफाफा चरित्र समृद्धि, एक फूल पूर्ण विकसित दिखने में उसके समान प्रतिनिधित्व करते हैं।चित्रलिपि धन (बॉक्स की तरह) के साथ लिफाफेअधिक एक निश्चित राशि के लिए कुछ भी संचय के लिए उपयुक्त हैं। इन सरल सिफारिशों के बाद और पुराने लक्षण को सुन कर, यह संभव है आप अपने नगदी प्रवाह को आकर्षित करने और इसे अपने परिवार के कल्याण के लिए रखना होगा।

यह व्यक्ति के जीवन मे प्रसिद्धि, सफलता और प्रतिभा की भविष्यवाणी करती है

यह रेखा व्यक्ति के जीवन मे प्रसिद्धि, सफलता और प्रतिभा की भविष्यवाणी करती है। सूर्य की रेखा को अपोलो रेखा, सफलता रेखा या प्रतिभा रेखा से भी जाना जा सकता है एवं यह हाथ के आकार पर निर्भर करता है । सूर्य रेखा द्वारा व्यक्ति के जीवन में ख्याति, सफलता और प्रतिभा की भविष्यवाणी की जा सकती है। सूर्य रेखा का उदय, जीवन रेखा, हदय रेखा, चंद्र पर्वत, मंगल स्थान या मष्तिष्क रेखा से होता है । सूर्य की रेखा का आकार, सफलता की सीमा का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यक्ति के जीवन में ख्याति, सफलता और ख्याति बनाए रखने में स्थिरता और उत्पन्न बाधाओं को बताता है । सूर्य रेखा के साथ मष्तिष्क रेखा अगर ढलती हुई जाती हैं तो इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति की सफलता कलात्मक क्षेत्र जैसे कविता, कला, साहित्य, कल्पनाशील पर आधारित क्षेत्र मे होती है। सूर्य रेखा के साथ कई महीन रेखाए ये दर्शाती है कि व्यक्ति कलात्मकता युक्त होता है परन्तु बहुविचारो के कारण वह किसी एक क्षेत्र मे सफलता नही प्राप्त कर पाता । सूर्य रेखा यदि स्पष्ट है तो व्यक्ति संवेदनशील, दयालु और उदार है इसका परिणाम उसे लोकप्रिय बनाता है । सूर्य की रेखा यदि असाधारण रुप से सीधी है तो व्यक्ति अपार धन का स्वामी, सामाजिक शक्ति प्राप्त करता है।

इस रेखा पर यदि तारा हो तो व्यक्ति प्रतिभावान होता है और उसकी स्थायी सफलता निश्चित है । सूर्य रेखा पर यदि वर्ग बना हो तो व्यक्ति अपने नाम और सामाजिक स्थिति के कारण दुश्मन के हमले से सुरक्षित होता है । कर्संदर्भ में दुश्मन के हमले के खिलाफ संरक्षण के संकेत सूर्य रेखा पर एक द्वीप की स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की निंदा होती है अंतत: एक लोकापवाद के रुप मे सामने आती है । एक प्रतिभाशाली और कलात्मक हाथ पर सूर्य की रेखा की अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की कडी मेहनत के बावजूद ख्याति प्राप्त करने मे मुश्किल आती है ।

यदि सूर्य रेखा बिखरी हुई भाग्य रेखा के साथ हो तो व्यक्ति निरंतर विफलताओं और निराशाओं के बावजूद सदैव खुश दिखाई देगा । यदि सूर्य रेखा के साथ भाग्य रेखा भी समानांतर चल रही हो साथ मे मष्तिष्क रेखा भी स्पष्ट हो तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है, और ऐसा व्यक्ति अपार धन का स्वामी, व्यवहारिक और भाग्यशाली होता है । यदि सूर्य की रेखा हाथ मे सपष्ट दिखाई दे और कुछ समय बाद लुप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्राय: दुखी रहता है लेकिन जब सूर्य की रेखा स्पष्ट होती है वो समय उसके लिये सुखमय होता है ।

यदि एक खोखले हाथ पर सूर्य रेखा विध्यामान हो तो ऐसा व्यक्ति निरंतर दुर्भाग्य होने के बावजूद सदेव आशावादी एव तेजस्वी प्रतीत होता है

सूर्य रेखा को अपोलो रेखा, सफलता की रेखा या बुद्धिमत्ता की रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा कलाई के पास चंद्र पर्वत से निकलकर अनामिका तक जाती है।

बेडरूम में झरने, तालाब की तस्वीर नहीं लगाएं

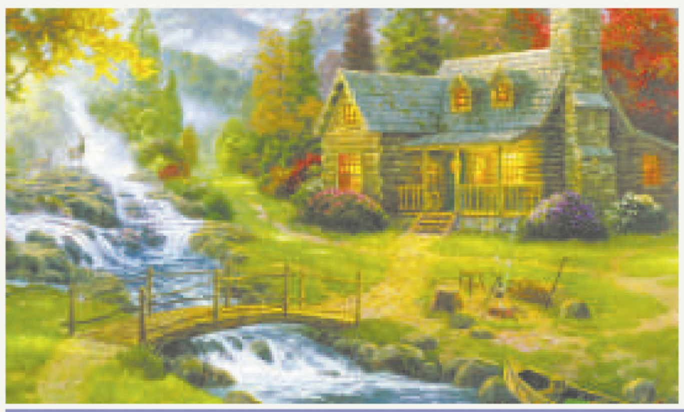

आपसी बातचीत शादीशुदा जिंदगी में रिश्तों की डोर को मजबूत बनाती है और टीवी और अन्य गैजेट्स इस बातचीत को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसलिए फेंगशुई के अनुसार अगर शादीशुदा जिंदगी में खुशियां चाहिए तो टीवी को बेडरूम से बाहर निकालना ही होगा। एक ही गदा हो, फेंगशुई के अनुसार पति-पत्नी के बेड पर एक ही गदा होना चाहिए। मसलन अगर डबल बेड है तो भी गद्दा एक ही फुल साइज होना चाहिए। दो गदों का प्रयोग वैवाहिक जोडे के भविष्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अलगाव नहीं संबंधों को दें जगह। पति-पत्नी के बेडरूम में अलगाव को दर्शाने वाली चीजें नहीं होना चाहिए। यहां नदी, तालाब, झरना और जल संग्रह आदि की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। पुराने रिश्तों को ना दें जगह, अगर पति-पत्नी में से किसी का पहले किसी अन्य से कोई रिश्ता हो तो उसे जुडी हर वस्तु बेडरूम से बाहर रखनी चाहिए। इस बात का ख्याल खासकर उन कपल्स को रखना चाहिए जिनकी या तो तलाक या पहली पति या पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी हुई हो। पानी वाली चीजें रखें बाहर। फेंगशुई के अनुसार पानी प्यार की ऊर्जा में बाधक का काम करता है, इसलिए बेडरूम में झरने, तालाब आदि की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही बेडरूम के अंदर किसी तरह का फव्वारा या मछलीघर भी नहीं रखना चाहिए।

पीने के लिए भी बस एक बोतल पानी रात के समय काफी है। बेडरूम में अपना बिस्तर खिडकी या दीवार से सटाकर कभी भी न लगाएं। इससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न होता है और आपसी असहयोग की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। घर को थोडा सजाएं, जिन युवाओं को अपना मनचाहा प्रेमी नहीं मिल रहा उन्हें सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। घर को सजाना पॉजिटिव एनर्जी को लाने का सबसे आसान तरीका होता है। घर की साफ-सफाई और सजावट में वक्त दीजिए। फेंगशुई के अनुसार सिंगल कुर्सियां और पक्षी, जानवरों की मूर्ति अकेलेपन को दर्शाती है, इसलिए सिंगल कुर्सियों को हटाएं। घर में जोडे वाले पक्षियों की तस्वीर या मूर्ति लगाए। इससे आपस में प्यार बढेगा। दक्षिण-पश्चिम कोना है बेहतर, फेंगशुई के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा ही प्यार का हिस्सा होता है। इस हिस्से को जितना हो सके सजा कर रखें।

फेंगशुई सिर्फवस्तुओं को सही जगह रखने का विज्ञान भर नहीं है, बल्कि इससे लव लाइफको भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें ऐसे कई टिप्स हैं जिसका पालन करके अविवाहित और विवाहित दोनों अपनी जिंदगी में लव का संचार कर सकते हैं। घर में टीवी, कंप्यूटर पर ज्यादा समय न दें बल्कि प्यार को जगाएं।

पेंटिंग बदल सकती है किस्मत

● **यदि** हम आस-पास तलाश करें, तो हर तरफनकारात्मकता दिखाई देगी। ऐसे में हम अपने घर में सकारात्मकता का प्रवेश लाने के लिए कुछ आसान से वास्तु उपाय आजमा सकते हैं। ऐसा करने पर आप अपने व्यवसाय और जिंदगी में तरक्की की नई सीढियां चढ सकते हैं।

● जीवित व्यक्ति की तस्वीर या पेंटिंग पश्चिम दिशा में और दिवंगतों की दक्षिण दिशा में होनी चाहिए।

घर में हमेशा उदय होते सूर्य की तस्वीर और पेंटिंग ही लगाएं। क्योंकि अस्त होता सूर्य नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है।

● घर में झाड़ू की वजह से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती है।

बच्चों की तस्वीर, लैंडस्केप या हरा-भरा जंगल आदि जैसे पेंटिंग या फेटो पश्चिम दिशा में लगाना उत्तम माना गया है।

● हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी के समान माना जाता है। ध्यान रखें घर का कोई भी सदस्य झाड़ू को पैर न लगाए। यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं।

● नवविवाहित जोडे की फोटो या पेंटिंग कमरे की उत्तर दिशा या उत्तर-दक्षिण कोने में लगानी चाहिए।

घर में पेंडुलम इसीलिए है जरूरी

परिवर्तन एक क्रियाशील शब्द है। जो जिंदगी में आगे बढने की सीख देता है। परिवर्तन यांग ऊर्जा को बढावा देता है। फेंगशुई में 'यांग' सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है।

यह नकारात्मक रूप से प्रवाहित हो रही 'चि' ऊर्जा को रोकने में सक्षम है। फेंगशुई विशेषज्ञों का मानना है, 'घर में पेंडुलम वाली घडी, छत के निचले सिरे पर पंखा और टेबल फेन जरूर उपयोग करना चाहिए।'

यह उपकरण आपको इस तरह लगाना चाहिए। जिससे परिवर्तन सा दृश्य हो यानी यह कमरे के दक्षिण क्षेत्र में ऊर्जा को प्रवाहित करें। पूर्व दिशा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है यह सेक्स और भविष्य निर्माण की शक्ति का संचय रखने में सक्षम है।

यदि ऊपर बताए गए उपकरणों के रंगों का चयन भी सकारात्मक रंगों जैसे पीला, हरा, केसरिया आदि के अनुरूप किया जाए तो यह और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं।

घर में भोजन कक्ष की ऐसी हो स्थिति

भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फेंगशुई के अनुसार यदि भोजन सही दिशा में बैठ कर सर्व किया जाए तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। भोजन बनाने की जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए। यहां मौजूद फर्नीचर को व्यवस्थित रखते हुए, डाइनिंग टेबल को कमरे के बीचों बीच ही रखें। ताकि ऊर्जा का प्रवाह ठीक तरह से हो। डाइनिंग टेबल यदि गोलाकार या अष्टकोणीय हो तो ज्यादा प्रभावशाली होती है। वर्गाकार या आयाताकार टेबल के कोने गोल होना चाहिए। यह बेहतर माना गया है। डाइनिंग टेबल के सामने आइना जरूर लगाएं। आईना कुछ इस तरह लगाइए कि खाद्य पदार्थ भी उसमें दिखाई देते रहें। ऐसा करने पर यह घर में अन्न का भंडार खत्म नहीं होने देते। यदि संभव हो सके तो किचिन में फलों और सब्जियों की पेंटिग्स या चित्र भी लगाएं। और टेबल पर फलों को सजाकर रखें। आपका फ्रीज भी सब्जियों और फलों से भरा होना चाहिए। ऐसा करने पर आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। चीनी फेंगशुई के अनुसार फुक, लुक और साऊ चीनी देवताओं की मूर्तियों को किचिन में लगाना अति सौभाग्यशाली जाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारी छात्र होंगे रिहा

नईदिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यह भी साफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। दिल्ली के गृह विभाग की ओर से जारी एक बयान में सरकार ने आगे कहा कि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा समीक्षा के बाद ही किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि एनसीटी दिल्ली सरकार का विरोध-प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ़ कोई और दंडात्मक कार्रवाई करने का इरादा नहीं है, और इस मामले को बिना किसी आगे की कार्रवाई के बंद माना जाएगा। यह आदेश एनसीटी दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल की मंजूरी से जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता है या नहीं, इस पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, ''संदर्भ (बड़ी पीठ के पास भेजने) के प्रश्न पर हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। आप अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।'' न्यायालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह की जमीन पर नमाज की दी इजाजत

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुस्लिम पक्ष को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह के परिसर में शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुसलमानों को शुक्रवार को अपराह्न एक बजे से तीन बजे के बीच उस जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हालांकि कहा कि इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार और मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति से शुक्रवार की नमाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं तलाश सकते। पीठ ने 14 जुलाई को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक धार में विवादित जगह के पास शुक्रवार को अपराह्न एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। बाद में, हाजी मुनीर अहमद की अगुवाई में मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

गिग कर्मियों को श्रम संहिता से मिलेगी सामाजिक सुरक्षाः मांडविया

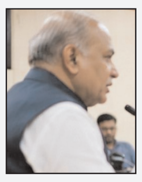

नईदिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार श्रम संहिता (श्रम कानूनों) के प्रावधानों को लागू कर गिग कर्मियों के हितों की रक्षा करेगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गिग कर्मी व्यवस्था एक नयी और उभरती हुई व्यवस्था है। मांडविया ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80 लाख गिग कर्मी हैं और उनमें से लगभग 10 लाख ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। मंत्री ने कहा कि श्रम संहिता के तहत, गिग कर्मियों को मान्यता दी गई है और उन्हें कानूनी दर्जा भी दिया गया है, जो कर्मचारियों के तौर पर उनके अधिकारों की रक्षा करने की सरकार की कोशिशों का हिस्सा है। गिग कर्मी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी रिश्ते से बाहर रहकर काम करता है या किसी काम की व्यवस्था में शामिल होता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।

राम मंदिर प्रबंधन में बदलाव की तैयारी

नईदिल्ली। अयोध्या के श्रीरामजन्मभूमि मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव और चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है. ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण परियोजना के प्रबंधक रहे इंजीनियर जगदीश आफले को नया सचिव नियुक्त करने का फैसाल लिया है. अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने जगदीश आफले का नाम प्रस्तावित होने की पुष्टि की है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज कर दी है. आईजी किरण एस. के नेतृत्व में बनी तीन सदस्यीय एसआईटी बैंककर्मियों के बयान दर्ज करने के बाद अब ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर रही है.नई एसआईटी के गठन के बाद जांच को फिर से गति मिली है और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. हालांकि, नई एसआईटी की औपचारिक बैठक अभी नहीं हुई है. लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.अनिल मिश्रा से हो सकती है पूछताछनई एसआईटी ने चढ़ावे की गणना करने वाले बैंककर्मियों के बयान दर्ज कर लिए हैं. अब पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा का बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

वेस्ट एशिया संकट पर सरकार सतर्क

पीएम मोदी ने सीसीएस कमेटी के साथ की हाई लेवल बैठक

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के नागरिकों और विदेशों में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं। साथ ही ऊर्जा और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने तथा भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

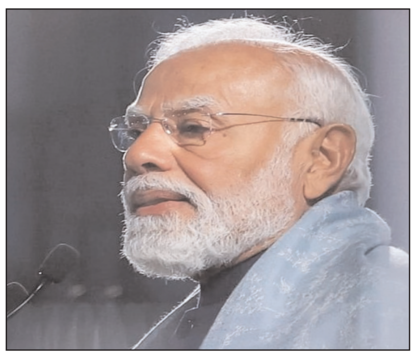

सीसीएस की बैठक बुलाने की क्या थी वजह?

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के प्रभावों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें ऊर्जा और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन किया गया। साथ ही भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

रबी सीजन के लिए उर्वरक को लेकर क्या तैयारी की गई?

बैठक के दौरान आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की संभावित आवश्यकता का आकलन किया गया। इसके अलावा उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उर्वरकों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे। इसके लिए सभी आवश्यक कदम समय रहते उठाए जाएं।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए क्या निर्देश दिए गए?

संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में गंभीरता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि नाविकों और उनके परिवारों को समय-समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने, आपातकालीन सहायता प्रदान करने तथा जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग की व्यवस्था के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। यह समीक्षा मिडिल ईस्ट क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों पर बढ़ते हमलों के मद्देनज़र की गई।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सौर ऊर्जा समेत अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया, ताकि भविष्य में बाहरी संकटों का असर देश पर कम से कम पड़े।

संकट से निपटने के लिए सरकार की क्या रणनीति होगी?

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को समन्वित तरीके से कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्णय तेजी से लागू किए जाएं तथा सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए।

कैबिनेट सचिव ने क्या जानकारी दी?

कैबिनेट सचिव ने बैठक में मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि एलएनजी, एलपीजी, उर्वरकों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एलपीजी आयात के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और देश में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार तथा आपूर्ति की स्थिति फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है।

पेट्रोलियम उत्पादन और गैस नेटवर्क को लेकर क्या स्थिति है?

उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां अपनी स्थापित क्षमता से भी अधिक उत्पादन कर रही हैं। इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस (क्ष्त्त) कनेक्शनों के विस्तार के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश में क्ष्त्त उपभोक्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

एलएनजी और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार क्या कर रही है?

कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विस्तार, एलएनजी आयात क्षमता और री-गैसीफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने तथा %पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर, 2026% के तहत निर्धारित समयसीमा में पाइपलाइन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मंजूरी देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इन प्रयासों से उद्योगों में एलपीजी के विकल्पों को अपनाने में भी मदद मिलेगी।

सदन में राहुल की बढ़ीं मुश्किलें? अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन और अवमानना का दिया नोटिस

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ बताया है।

अनुराग ठाकुर ने तीन पन्नों के नोटिस में लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समिति इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करे। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी को सदन और गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। भाजपा सांसद का कहना है कि इस तरह की भाषा संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

राहुल गांधी पर कौन से नियम के उल्लंघन का आरोप?

नोटिस में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 29 जुलाई को एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कथित बातचीत का जिक्र किया। उनका आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा के नियम 352 का उल्लंघन किया। नोटिस में कहा गया कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जो प्रमाणित नहीं थे और जिनसे सदन की गरिमा प्रभावित हुई।

विशेषाधिकार समिति से क्या मांग की गई?

अनुराग ठाकुर ने अपने नोटिस में कहा कि मामले की पूरी जांच विशेषाधिकार समिति से कराई जाए। उनका कहना है कि समिति यह तय करे कि राहुल गांधी की टिप्पणी से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ या नहीं। उन्होंने समिति से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी आग्रह किया है, ताकि भविष्य में सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय मर्यादा बनी रहे।

अब इस मामले में आगे क्या होगा?

लोकसभा अध्यक्ष के पास नोटिस पहुंचने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संसदीय नियमों के अनुसार होगी। अध्यक्ष यह तय करेंगे कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है तो समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे सकती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

राहुल के इडियट वाले बायन पर क्या बोले थे अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन के बाहर बुधवार को राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था अगर राहुल गांधी ने किसी छात्र के लिए %इडियट% शब्द का इस्तेमाल किया है तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने यह शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि हम इसका स्वागत करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है कि राहुल गांधी को अब इसका एहसास हो गया, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह टिप्पणी एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान के बाद की।

खेल
प्रमुख समाचार

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

मुंबई। भारत के अनुभवी बल्लेबाज और 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार (30 जुलाई) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वह अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी खेलते नहीं दिखाई देंगे। पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। रहाणे ने साफ कहा कि वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया और संन्यास का एलान किया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, कैप नंबर 278 अब यहीं तक। वर्षों तक मिले आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। रहाणे ने कहा, जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और हर चीज का अंत भी होता है। जब वह समय आता है तो उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बल्लेबाजी में मैंने हमेशा सही टाइमिंग पर भरोसा किया है और आज मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए यही सही समय है। रहाणे ने अपने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए कहा, डोंबिवली से एक छोटे लड़के के रूप में सिर्फ अभ्यास करने के लिए सफर शुरू किया था। हर दिन, हर पारी और बल्लेबाजी का हर मौका मेरे लिए भारत की कैप पहनने के सपने से जुड़ा था। मैंने हमेशा एक ही नियम अपनाया, अपने देश और टीम को खुद से ऊपर रखा। उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से क्रिकेट खेला। मेरा मानना रहा कि अगर आपकी नीयत सही है तो खेल आपका साथ जरूर देता है। पिछले 20 वर्षों में भारतीय क्रिकेट का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात रही।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 274 अंक उछला निफ्टी 24,317 पर बंद

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर निवेशकों की नजर बनी रही, जिसके चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। दिनभर उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार के बाद प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि, व्यापक बाजार में दबाव देखने को मिला और मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 273.55 अंक यानी 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 77,928.15 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 66.95 अंक यानी 0.28 फीसदी चढ़कर 24,317.15 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया और आयशर मोटर्स के शेयर सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में शामिल रहे। इन शेयरों की मजबूती ने प्रमुख सूचकांकों को सकारात्मक स्तर पर बंद होने में मदद की।

1 अगस्त से फिलहाल नहीं बदलेंगे ई-वे बिल के नियम

नईदिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल सिस्टम में प्रस्तावित बदलावों को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है। ये बदलाव 1 अगस्त से लागू होने वाले थे। इंडस्ट्री की ओर से टेक्निकल सिस्टम और कारोबारी प्रक्रियाओं की तैयारियों को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद यह फैसला लिया गया है। ई-वे बिल जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित मूल्य से ज्यादा के सामान की आवाजाही के लिए तैयार किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। बुधवार को जारी एक एडवाइजरी में जीएसटीएन ने कहा कि करदाताओं को पहले जारी की गई एडवाइजरी के आधार पर अपनी प्रणालियों में फिलहाल कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आगे की सूचना मिलने तक मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।

भारत-जर्मनी रक्षा सौदा, जल्द होगी पनडुब्बी डील साइन

नई दिल्ली। भारत और जर्मनी 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक पनडुब्बी डील पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने पुष्टि की कि प्रोजेक्ट-75आई के तहत छह अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता अगले महीने तक अंतिम रूप ले सकता है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत सभी छह नेक्स्ट-जेनरेशन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई स्थित सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें जर्मन डिफेंस दिग्गज थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स मुख्य तकनीकी भागीदार के रूप में सहयोग करेगी। ये पनडुब्बियां एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस होंगी। यह तकनीक पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए लगातार दो सप्ताह तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देती है।

प्रेस्टीज एस्टेट्स का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 19% घटा

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 19 प्रतिशत घटकर 235.9 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 292.5 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,835.6 करोड़ रुपए हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 2,468.7 करोड़ रुपए थी। रियल एस्टेट कंपनी ने अलग से एक नियामकीय सूचना में ठाणे में एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी करने की जानकारी दी है। हालांकि, उसने भू-स्वामी के नाम का खुलासा नहीं किया।

बांग्लादेश से व्यापार के लिए पुतिन ने भारतीय रुपए पर लगाया दाँव

नीरज कुमार दुबे

रूस ने बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने का प्रस्ताव देकर दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में नई हलचल पैदा की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने राजदूत सर्जियो गोर को तुरंत ढाका जाने का निर्देश दे डाला। इन दोनों घटनाक्रमों को साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। एक ओर रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत की वित्तीय ताकत का सहारा लेकर बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ना चाहता है, वहीं दूसरी ओर चीन और रूस के साथ ढाका की बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने अपने शीर्ष राजनयिक को ढाका भेजने का फैसला किया है। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रुपया, क्षेत्रीय कूटनीति और हिंद-प्रशांत की बदलती रणनीतिक राजनीति एक साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

हम आपको बता दें कि रूस ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार भारतीय रुपये में निपटाया जाए। इसके साथ ही मॉस्को एक विशेष भुगतान तंत्र विकसित करने, ढाका में रूसी बैंक की शाखा खोलने तथा प्रत्यक्ष बैंकिंग संपर्क स्थापित करने की भी पहल कर रहा है। यह प्रस्ताव रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों से उत्पन्न वित्तीय संकट का सीधा जवाब है। प्रतिबंधों के कारण रूसी बैंक वैश्विक भुगतान प्रणाली से काफी हद तक कट गए हैं और इसी वजह से मॉस्को चीन, तुर्किये और भारत जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूस ने चीनी युआन की बजाय

भारतीय रुपये को प्राथमिकता दी है। इससे पहले रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के ऋण भुगतान के लिए युआन का विकल्प सामने आया था, लेकिन चीन और बांग्लादेश के बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम के कारण भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा बनने से हिचक गए। परिणामस्वरूप अरबों डॉलर की ऋण किस्तें अभी भी सोनाली बैंक में रूस के नाम खोले गए खाते में फंसी हुई हैं। ऐसे में भारतीय रुपया रूस के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है। यह भारत की वित्तीय विश्वसनीयता और रुपये के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी संकेत है।

बताया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में होने वाली बांग्लादेश-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि रूस केवल भुगतान व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रूस-बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल, वस्त्र निर्यातकों का पंजीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सहयोग तथा कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का भी प्रस्ताव लेकर आया है। मॉस्को ने बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय बाजार से 10 डॉलर प्रति टन कम कीमत पर लगभग 2.8 लाख टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में भी रुचि दिखाई है। दूसरी ओर ढाका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार, कृषि, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को अपनी प्राथमिकता बना रहा है।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से यह घटनाक्रम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि रूस और बांग्लादेश के बीच व्यापार भारतीय रुपये में होता है, तो यह दक्षिण एशिया में रुपये के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को नई गति देगा। इससे डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम होगी और भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय सेतु के रूप में उभर सकता है। यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति के भी अनुकूल है जिसके तहत वह रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र के निर्माण पर जोर दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सर्जियो गोर का 30 जुलाई का ढाका दौरा विशेष महत्व प्राप्त करता है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की पहल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक

महानदी विवाद नहीं, छत्तीसगढ़-ओडिशा की साझा समृद्धि का आधार बने : सीएम साय

रायपुर । महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में आज नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा तथा उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख एवं व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय-समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे।मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर अधिकतम विषयों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए तथा केवल नीतिगत महत्व के विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर विचार के लिए लाया जाए।

शिक्षा जीवन बदलने की सबसे बड़ी ताकत: वित्त मंत्री

रायपुर। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत पुसौर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव-2026 उत्साह, उल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन का भूमिपूजन किया। साथ ही नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया तथा उन्हें पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि विद्यालय में पहला कदम किसी भी बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत होता है। शिक्षा केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की दिशा और दशा बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासित जीवन और सतत मेहनत के बल पर उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय किया। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन का लक्ष्य अभी से निर्धारित करने और उसी दिशा में समर्पित होकर मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह तय होना चाहिए कि जीवन में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के द्वार खुले हैं और ऐसे अवसरों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुँचाना शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय संस्थानों में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

जलापूर्ति के लिए जल संचय और जल संरक्षण जरूरी : अरुण साव

पीएचई द्वारा यूनिसेफ और एसीई के सहयोग से हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों के लिए कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों के लिए ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यशाला में महिला सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि जल आपूर्ति की योजनाओं के लंबे समय तक सुचारू संचालन के लिए बारिश के पानी का संचय और जल संरक्षण आवश्यक है। यह भूजल को रिचार्ज करने के साथ ही दीर्घ काल तक जल स्त्रोतों में जल की उपलब्धता बनाए रखेगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यशाला में सरपंचों से गांवों में हर घर नल से जल पहुंचने के बाद ग्रामीणों, खासकर महिलाओं के जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने नल जल योजनाओं के संचालन-संधारण के लिए पंचायतों द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने गांवों में जलस्त्रोतों, जल की गुणवत्ता के नियमित परीक्षण तथा रखरखाव शुल्क की भी जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यूनिसेफ और एसीई संस्था के सहयोग से इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 100 महिला सरपंच शामिल हुईं। कार्यशाला में हर घर जल प्रमाणित गांवों में नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और मरम्मत पर व्यापक विचार-विमर्श और बेस्ट प्रेक्टिसेस पर गहन चर्चा की गई। महिला सरपंचों ने इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत अपनी-अपनी पंचायतों में जल आपूर्ति की व्यवस्था तथा नल जल योजना के संचालन-संधारण के अनुभव साझा किए। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महिला सरपंचों को नल जल योजनाओं के सफल, निर्बाध और दीर्घकालीन संचालन के गुर बताए।

2026 युवाओं के सुरक्षित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम: वित्त मंत्री चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया है। श्री चौधरी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और उनकी योग्यता की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं। प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा माफिया और अनुचित साधनों के माध्यम से होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह संशोधन अत्यंत आवश्यक था। इसके लागू होने से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी तथा ईमानदार एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए यह एक नया अध्याय है। यह संशोधन परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा तथा संगठित परीक्षा अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।श्री चौधरी ने इस युगांतकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। यह विधेयक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

स्कूलों में 1098 हेल्पलाइन अंकित करना अनिवार्य: अध्यक्ष डॉ. वर्णिका

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने प्रदेश में बच्चों के समग्र विकास, सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। धमतरी जिला मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि खेल मैदानों का किसी भी स्थिति में व्यावसायिक उपयोग नहीं होना चाहिए। जिन मैदानों का अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें तत्काल मुक्त कराकर बच्चों के खेलकूद के लिए उपलब्ध कराया जाए। बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ सहित पुलिस, शिक्षा एवं बाल संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ड्रॉपआउट बच्चों की निगरानी

प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों की दीवारों और प्रमुख स्थलों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों में स्कूल छोड़ने वाले (ड्रॉपआउट) बच्चों का घर-घर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा बाल श्रम, बाल विवाह या मानव तस्करी का शिकार न हो। इसी तरह बुनियादी सुविधाओं पर जोर देते हुए उन्होंने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल और बेहतर खेल सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।पुलिस विभाग को पॉक्सो मामलों को लेकर समाज में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी का विवरण प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण देना सरकार और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। बच्चों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञात हो कि धमतरी जिला में खेल एवं युवा कल्याण द्वारा जिले के 81 मिनी स्टेडियमों में खेल गतिविधियां जारी हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

बस्तर की विश्वविख्यात हस्तशिल्प कला को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रायपुर स्थित द वाहे , अंबुजा मॉल के सामने, विधानसभा रोड में 'द लोकल मेकर्स मार्केट-2026' का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विशेष 'बस्तर पवेलियन' स्थापित किया जाएगा, जिसमें बस्तर अंचल की विश्वप्रसिद्ध ढोकरा शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, जनजातीय कलाकृतियों तथा हाथकरघा बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा।ग्रामोद्योग विभाग का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को राष्ट्रीय स्तर पर विपणन का अवसर उपलब्ध कराना तथा छत्तीसगढ़ की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को व्यापक पहचान दिलाना है। तीन दिवसीय इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से 80 से अधिक हस्तशिल्प उद्यमी एवं कलाकार भाग लेंगे। विभाग द्वारा 20 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से प्रदेश के शिल्पकारों को नए बाजार, संभावित खरीदारों एवं डिज़ाइन विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री राजेश सिंह राणा ने कहा कि बस्तर की हस्तशिल्प परंपरा राज्य की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। राज्य शासन निरंतर ऐसे प्रयास कर रहा है, जिनसे स्थानीय कारीगरों को उनकी कला के अनुरूप पहचान और सम्मान प्राप्त हो।

वीएसके ऐप में त्रुटियों का होगा शीघ्र समाधान: शिक्षा मंत्री

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों द्वारा ङ्कस्य ऐप में आ रही तकनीकी त्रुटियों एवं एरर संबंधी शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ङ्कस्य ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री यादव ने बताया कि संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को ङ्कस्य ऐप में आ रही सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 अगस्त तक ऐप में आ रही तकनीकी खामियों का समाधान कर इसे पूरी तरह सुचारु बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिल सके। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से लगभग डेढ़ लाख शिक्षक लगभग 85 प्रतिशत शिक्षक प्रतिदिन ङ्कस्य ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

31 को श्री राम मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के निमित्त आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से पवित्र माटी एवं जल लेकर निकला भाजपा का प्रतिनिधिमण्डल कल 31 जुलाई को राजधानी पहुँचेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संत रविदास जयंती कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अखिलेश सोनी ने यह जानकारी दी। भाजपा प्रदेश महामंत्री सोनी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि संत रविदास के समरस समाज के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए यह पवित्र कलश अगले चरण में प्रदेश के सभी जिलों में जाएगा। श्री सोनी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने समाज से भेदभाव को मिटाकर बंधुत्व और समरसता का मार्ग दिखाया था। उनकी 650वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी का स्वागत अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में निरंतर चलाया जाएगा। श्री सोनी ने बताया कि अम्बिकापुर में भव्य स्वागत के पश्चात यह यात्रा जगह-जगह जन-अभिनंदन स्वीकार करते हुए बिलासपुर पहुँचेगी। बिलासपुर में रात्रि विश्राम के बाद कल 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे बंजारी माता मंदिर रायपुर पहुँचेगा एवं शहर की प्रमुख स्थानों से होते हुए दोपहर 1 बजे यह यात्रा राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर पहुँचेगी जहाँ पूज्य साधु-संतों की गरिमामय उपस्थिति में पवित्र कलश, वाराणसी की माटी का विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया जाएगा।

गुरु पूर्णिमा पर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ ने किया पौधरोपण

रायपुर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ द्वारा सरोना स्थित कार्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक एवं रायपुर संभाग प्रभारी श्री संदीप अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संवर्धन एवं मातृ सम्मान का संदेश देते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया।संदीप अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि माँ के प्रति श्रद्धा, सम्मान और प्रकृति संरक्षण का एक जन-आंदोलन है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करे, तो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक हरित एवं सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ ने प्रदेशवासियों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री के विजन को रेखांकित करेगी 'मुस्कुराता बस्तर' कार्टून कार्यशाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच द्वारा जगदलपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए 'मुस्कुराता बस्तर' थीम पर विशेष कार्टून कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला का प्रशिक्षण देने के साथ बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और लोकजीवन को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर आज विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों के कारण देश-दुनिया में नई पहचान बना रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा तथा अन्य लोकपर्व बस्तर की समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। कार्टून वॉच के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि कार्यशाला की थीम 'मुस्कुराता बस्तर' इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को कार्टून कला के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति देना है।

सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

बस्तर में सड़क विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर । दिल्ली प्रवास के दौरान बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री महेश कश्यप ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे। सांसद श्री कश्यप ने बस्तर में सड़क संपर्क को मजबूत करने, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सांसद श्री कश्यप ने बताया कि सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों और प्रभावी रणनीति के कारण बस्तर में नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उद्योग, व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक और बेहतर सड़क नेटवर्क आवश्यक है।

फोरलेन बनाने का प्रस्ताव

बस्तर सांसद ने एनएमडीसी स्टील प्लांट की गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जगदलपुर-नगरनार-ओडिशा सीमा मार्ग को फोरलेन बनाने की मांग की। इसके साथ ही जगदलपुर-दंतेवाड़ा-बीजापुर-भोपालपटनम-तेलंगाना सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग को भी फोरलेन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात तक पर्यटकों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग को भी चार लेन में विकसित करने की मांग की।

भारतमाला परियोजना से जोड़ने पर जोर

बस्तर सांसद श्री कश्यप ने जगदलपुर को भारतमाला परियोजना के आर्थिक गलियारों से जोड़ने, शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड और बायपास के निर्माण तथा बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए विशेष विकास पैकेज स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, आवश्यक स्थानों पर पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का विषय भी प्रमुखता से उठाया।

बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बस्तर में व्यापार, रोजगार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी। इससे बस्तर राष्ट्रीय विकास के मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा।

सरोना में एकदिवसीय नि:शुल्क दंत चिकित्सा शिविर आयोजित

रायपुर। उमंग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, सरोना में एकदिवसीय नि:शुल्क दंत चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 150 विद्यार्थियों के दांतों का परीक्षण किया गया तथा उन्हें दांतों की नियमित देखभाल, स्वच्छता एवं मौखिक स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

शिविर में डॉ. वृंदा सिंह एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों का दंत परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा कार्य की सभी ने प्रशंसा की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह संयोजक एवं रायपुर संभाग प्रभारी श्री संदीप अग्रवाल तथा जिला सह संयोजक श्री आशीष कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर उमंग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक श्रीमती वंदना सिंह ने कहा कि संस्था भविष्य में रायपुर के विभिन्न विद्यालयों में नि:शुल्क दंत चिकित्सा शिविर एवं कैरियर काउंसलिंग कक्षाओं का आयोजन करेगी, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके भविष्य के मार्गदर्शन में भी सहायता मिल सके।कार्यक्रम के सफल आयोजन में शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, सरोना के प्राचार्य श्री रविशंकर सोनी का विशेष सहयोग रहा, जिसके लिए उमंग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने उनका आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, चिकित्सकों एवं सहयोगियों का सम्मान किया गया तथा समाजहित में ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.